रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED NO. D. (D.)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 9, 1978/अग्रहायण 8, 1900

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER, 9 1978/AGRAHAYANA 8, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1978

सा० का० नि० 3489:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के सेवारत व्यक्तियों के सम्बन्ध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) संशोधन नियम, 1978 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 में, नियम 5 के उप नियम (2)(क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

"(2)(क) जहां नियुक्ति प्राधिकारी किसी अस्थायी सरकारी सेवक की सेवा समाप्त करते हुए कोई सूचना (नोटिस) देता है या जहां ऐसी सूचना की अवधि पूर्ण हो जाने पर या वेतन और भत्तों का तुरन्त संदाय कर के ऐसे सरकारी सेवक की सेवा समाप्त कर दी जाती है, वहां केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी या यदि ऐसा प्राधिकारी उसके अधीनस्थ है तो विभागाध्यक्ष अपने आप या अन्यथा मामले की कार्यवाही पुनः आरंभ कर सकता है और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है :

(i) नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि

(ii) नोटिस वापिस लिया जाना ।

(iii) सरकारी कर्मचारी को सेवा में बहाल करना अथवा

(iv) उक्त मामले में ऐसा अन्य आदेश जारी करना जैसा वह उचित समझे ।

बशर्ते कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, जो लिखित रूप में रिकार्ड की जायेंगी —

(क) (i) जिस मामले में नोटिस दिया गया है वहां नोटिस की तारीख से ।

(ii) जिस मामले में कोई नोटिस नहीं दिया गया है वहां सेवा समाप्त किये जाने की तारीख से,

3 मास समाप्त होने के बाद इस उप नियम के अधीन किसी केस को दुबारा नहीं उठाया जायेगा ।"

[सं० 12015/1/77-स्थापना (ग)]

आर० सी० गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 3rd November, 1978

G.S.R. 3489.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause(5) of the article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and

Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services Temporary Service) Rules, 1965 namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Temporary Service) Amendment Rules, 1978.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, for sub-rule (2)(a) of rule 5, the following shall be substituted, namely :—

"(2) (a) Where a notice is given by the appointing authority terminating the services of a temporary Government servant or where the service of any such Government servant is terminated on the expiry of the period of such notice or forthwith by payment of pay plus allowance the Central Government or any other authority specified by the Central Government in this behalf or a head of Department, if the said authority is subordinate to him, may, of its own motion or otherwise, reopen the case and after making such enquiry as it deems fit —

(i) confirm the action taken by the appointing authority ;

(ii) withdraw the notice ;

(iii) reinstate the Government servant in service; or

(iv) make such other order in the case as it may consider proper.

Provided that except in special circumstances, which should be recorded in writing, no case shall be re-opened under this sub-rule after the expiry of three months—

(a)(i) from the date of notice, in a case where notice is given ;

(ii) from the date of termination of service, in a case where no notice is given".

[No. 12015/1/77-Estt. (c)]

R. C. Gupta, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1978

का० आ० 3490—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा-(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करके एतद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट अपराधों की जांच करने के बारे में शक्तियों तथा अधिकार क्षेत्रों का असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों तक विस्तार करती है :

अनुसूची

1. पुरावशेष तथा बहुमूल्य अनुसूची कलाकृति, अधिनियम, 1972 (1972 का 52) की धारा 25 के अधीन दण्डनीय अपराध ; और

2. ऊपर पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी एक या अधिक अपराधों के संबंध में या उस सिलसिले में प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षडयंत्रों तथा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न कार्य सम्पादन के दौरान किए गए कोई अन्य अपराध ।

[सं० 228/13/76-ए० वी० डी० (ii)]

New Delhi, the 22nd November, 1978

S.O. 3490.—In exercise of hte powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government, having obtained the consent of the Government of the States concerned, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment in respect of the investigation of the offences specified in the Schedule below, to the State of Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghlaya, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal.

SCHEDULE

1. Offences punishable under Section 25 of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972).

2. Attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with one or more of the offences mentioned in paragraph I above, and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/13/76-AVD. II]

नई दिल्ली 23 नवम्बर, 1978

का० आ० 3491—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, देहरादून, लखनऊ, इलाहाबाद में विचारण, अपीलीय तथा पुनरीक्षण न्यायालयों में श्री जे० स्वरूप, संयुक्त सचिव, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून तथा अन्य के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना नियमित मामला संख्या 4/77-सी आई यू (ए) में अभियोजन तथा उससे उत्पन्न किसी अन्य मामले का भी संचालन करने के लिए श्री पी० के० चौबे, अधिवक्ता, वाराणसी को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 225/58/78-ए० वी० डी०-2]

टी० के० सुब्रमणियन, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd November, 1978

S.O. 3491.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri P. K. Chaube Advocate, Varanasi as a Special Public Prosecutor for conducting the prosecution and also any other matter arising out of the Delhi Special Police Establishment Regular Case No. 4/77-CIU(A) against Shri J. Swarup, Joint Director, Oil and Natural Gas Commission, Dehradun and others in the trial, appellate and revisional Courts in Dehradun/Lucknow/Allahabad.

[No. 225/58/78-AVD. II]

T. K. SUBRAMANIAN, Under Secy.

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1978

का० आ० 3492—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित विभागों को जिसके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

(1) वार्षिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग सहित)

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(3) भारी उद्योग विभाग

(4) नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष)

(6) गृह मंत्रालय

[संख्या 12022/1/78 रा भा (ख-2)]

हरिबाबू कंसल, उप सचिव

Department of Official Language)

New Delhi, the 24th November, 1978

S.O. 3492.—In pursuance of Sub-section (4) of rule 10 of the Official Language (use for Official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following Departments, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

(1) Department of Economic Affairs (including Banking Division)

(2) Ministry of Health and Family Welfare.

(3) Department of Heavy Industry.

(4) Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing)

(5) Ministry of Home Affairs.

[No. 120022/1/78-O.L(B-2)]
H. B. KANSAL, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1978

आयकर

का०आ० 3493.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को, विहित प्राधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया है।

संस्था

भारत का पोटाश अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

यह अधिसूचना, 1-4-1978 से 31-3-1980 तक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 2451/फा० सं० 203/36/77-आ०क० अ० 2]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 2nd August, 1978

INCOME-TAX

S.O. 3493.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (I) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

Potash Research Institute of India, New Delhi.

This notification is effective for a period of two years from 1-4-1978 to 31-3-1980.

[No. 2451/F. No. 203/36/77-ITA. II]

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1978

शुद्धिपत्र

का०आ० 3494.—राजस्व विभाग अधिसूचना सं० 2451 [फा० सं० 203/36/77-आई टी ए 2], तारीख 2 अगस्त, 1978 को निम्नलिखित रूप में संशोधित करता है —

"यह अधिसूचना 1-4-1978 से 31-3-1980 तक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है" के स्थान पर "यह अधिसूचना 2 मार्च, 1977 से, 31-3-1980 तक प्रभावी है।" पढ़ें

[सं० 2514(फा० सं० 203/36/77-आईटी ए 2)]

New Delhi, the 21st September, 1978

CORRIGENDUM

S.O. 3494.—The Department of Revenue hereby amend the notification No. 2451 (F. No. 203/36/77-ITA.II) dated 2nd August, 1978 as under :—

For	*Read*
This notification is effective for a period of two years from 1-4-1978 to 31-3-1980.	This notification is effective from 2nd March, 1977 to 31-3-1980.

[No. 2514/F. No. 203/36/77-ITA.II)]

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 1978

शुद्धिपत्र

का०आ० 3495.—राजस्व विभाग अधिसूचना सं० 2101 [फा०सं० 203/6/77-आ० का० आ० 2] तारीख 4-1-1988 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

(i) आरंभ होने की प्रस्तावित तारीख 1 सितम्बर, 1977 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें अर्थात्:—

"आरंभ होने की प्रस्तावित तारीख 1-4-1978"

(ii) पूर्ण होने की अनुमानित तारीख 30-8-1982 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें अर्थात् :—

"पूर्ण होने की अनुमानित तारीख 31-3-1979"

[सं० 2542/फा० सं० 203/6/77-आ०का०आ० 2]

New Delhi, the 9th October, 1978

CORRIGENDUM

S.O. 3495.—The Department of Revenue hereby amend the notification No. 2101 (F. No. 203/6/77-ITA.II) dated 4-1-1978 as under :—

For	*Read*
Proposed date of commencement 1st Sept, 1977	Proposed date of commencement 1-4-1978
Anticipated date of completion 30-8-1982.	Anticipated date of completion 31-3-1979.

[No. 2542/F. No. 203/6/77-ITA.II]

का०आ० 3496.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान

परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक् से रखेगी।

(ii) उक्त संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की एक वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष अधिक से अधिक 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं।

संस्था

कैंसर अनुसंधान संस्थान, नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज एवं अस्पताल सुश्रुतनगर जिला, दार्जिलिंग।

यह अधिसूचना 14-8-1978 से 13-8-1980 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त होगी।

[सं० 2540/फा० सं० 203/177/77 आई टी ए 2]

S.O. 3496.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (I) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6(iii) of the Income Tax Rules 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research, subject to the following conditions :—

(1) That the institution will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.

(2) That the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council for each financial year by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

The Institute for Cancer Research, North Bengal Medical College & Hospital, Sushrutanagar, Distt. Darjeeling.

This notification is effective for a period of 2 years from 14-8-1978 to 13-8-1980.

[No. 2540/F. No. 203/177/77-ITA. II]

का०आ० 3497.—इस विभाग की अधिसूचना सं० 1078 [फा० सं० 203/62/75-आ० क० अ० 2] तारीख 9 सितम्बर, 1975 के अनुक्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था का अनुमोदन आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी अर्थात् भारतीय समाज विज्ञान, अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, 1-4-1978 से 3 वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

संस्था

समाज कल्याण एवं विकास में अनुसंधान तथा दस्तावेजी केन्द्र, मुम्बई।

यह अधिसूचना 1-4-1978 से 31-3-1981 तक, की तीन वर्ष की और अवधि तक प्रभावी रहेगी।

[सं० 2541/फा० सं० 203/110/78-आ०क०अ० 2]

जे० पी० शर्मा, निदेशक

S.O. 3497.—In continuation of this Department's Notification No. 1078 (F.No. 203/62/75-ITA.II) dated 9th September, 1975, it is hereby notified for general information that the approval to the institution mentioned below has been extended by Indian Council of Social Science Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (I) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the conditions as mentioned therein for a further period of 3 years with effect from 1-4-1978.

INSTITUTION

The Research & Documentation Centre In Social Welfare and Development, Bombay.

This notification is effective for a further period of 3 years from 1-4-1978 to 31-3-1981.

[No. 2541/F. No. 203/110/78-ITA. II]

J. P. SHARMA, Director

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1978

सीमा-शुल्क

का. आ. 3498.—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 75/75-सीमाशुल्क, तारीख 3 जुलाई, 1975 (12 आषाढ़, 1897 शक) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं. 4 के सामने स्तंभ 3 में,—

(क) प्रविष्टि (17) में "चार्टरित उड़ानों से" शब्दों का लोप किया जाएगा,

(ख) प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त : स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(10) पुस्तकें, मुद्रित सामग्री, जिसके अन्तर्गत ओरख, ब्लू प्रिन्ट और रेखाचित्र भी हैं।

(21) तार-कर्षण, हीरक डाइ।

(22) द्रुतशीतित मांस।"

[सं. 233/78 सीमा-शुल्क/फा. सं. 481/61/78-सीमाशुल्क]

एन. कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

New Delhi, the 9th December, 1978

CUSTOMS

S.O. 3498.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 75/75-Customs dated the 3rd July, 1975 (12th Asadha, 1897 Saka), namely :—

In the Table annexed to the notification, against Serial Number 4, in column 3, (a) in entry (xvii), the words "by chartered flights" shall be omitted;

(b) after the entries, the following entries shall be inserted, namely :—

"(xx) Books, printed material including diagrams, blue prints and drawings ;

(xxi) Wire-drawing diamond dies ;

(xxii) Chilled meat."

[No. 233/78-Customs/F. No. 481/61/78-Cus. VII]
N. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1978

आय-कर

का० आ० 3499.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "अरुलमिगु अरुणाचलेश्वरर टेम्पल, थिरुवन्नामलाई" को निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2544/फा० सं० 197/134/77-आ० क०(ए०-I)]

New Delhi, the 9th October, 1978

INCOME-TAX

S.O. 3499.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Arulmigu Arunachaleswarar Temple, Thiruvannamalai" for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1975-76.

[No. 2544/F. No. 197/134/77-IT(AI)]

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1978

आय-कर

का० आ० 3500.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री अहोबिला मठ तमिल नाडु" को निर्धारण वर्ष 1971-72 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2548/फा० सं० 197/49/78-आ० क०(ए-I)]

New Delhi, the 18th October, 1978

INCOME-TAX

S.O. 3500.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Ahobila Mutt, Tamil Nadu" for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1971-72.

[No. 2548/F. No. 197/49/78-IT(AI)]

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1978

आय-कर

का० आ० 3501.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "कोचीन देवास्वम् बोर्ड, त्रिचूर" को निर्धारण वर्ष 1972-73 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2567/फा० सं० 197/152/78—आ० क०(ए-I)]

New Delhi, 30th October, 1978

INCOME-TAX

S.O. 3501.—In exercise of he powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Cochin Devaswom Board, Trichur" for the purpose of the said section for and from the assessment year 1972-73.

[No. 2567/F. No- 197/152/78-IT(AI)]

आय-कर

का० आ० 3502.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री जैन श्वेताम्बर भण्डार तीर्थ राजगीर" को निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2565/फा० सं० 197/25/78—आ० क०(ए-I)]

INCOME-TAX

S.O. 3502.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Jain Swetamber Bhandar Tirth Rajgir" for the purpose of the said section for and from the assessment year 1973-74.

[No. 2565/F. No. 197/25/78-IT(AI)]

आय-कर

का०आ० 3503.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री 108 प्राणनाथ मन्दिर ट्रस्ट धाम, पन्ना" को निर्धारण वर्ष 1977-78 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2566/फा० सं० 197/90/77—आ० क०(ए-I)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

INCOME-TAX

S.O. 3503.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri 108 Prannath Mandir Trust Dham, Panna" for the purpose of the said section for and from the assessment year 1977-78.

[No. 2566/F. No. 197/90/77-IT(AI)]
M. SHASTRI, Under Secy.

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 27 मई, 1978

आयकर

का० आ० 3504.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने के लिए सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० 1 (एफ० सं० 55/233/63-आई टी) तारीख 18-5-1964 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्धन करता है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में, क्रम० सं० 86 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

अनुसूची

क्रम सं०	व्यक्ति	आ० अ०	स० नि० आ०	स० प्र० आ०	आ० आ०
1	2	3	4	5	6
"87.	पटसन माल के सभी विनिर्माता, पटसन माल के सभी व्यवहारी, कच्चे पटसन के सभी व्यवहारी, कच्चे माल के सभी दलाल और कच्चे पटसन के सभी दलाल जिनके कारबार के स्थान कलकत्ता नगर, 24 परगना के सिविल जिला और हावड़ा में है किन्तु इसमें ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या मामले या मामलों के वर्ग सम्मिलित नहीं है जो उन प्रवर्गों में आते हैं जो कलकत्ता के निम्नलिखित आयकर सर्किल जिलों को विनिर्दिष्ट रूप से समनुदिष्ट किए गए हैं और जो भविष्य में समनुदिष्ट किए जाएंगे; (i) केन्द्रीय सर्किल, कलकत्ता (ii) जिला पी (2), कलकत्ता (शीघ्र विशेष जांच सर्किल-III, कलकत्ता के रूप में पुनः अभिहित किया जाएगा) और (iii) विदेशी कम्पनियां सर्किल I और II कलकत्ता	पटसन सर्किल, कलकत्ता के सभी आ० आ० (क से च वार्ड)	सहायक आयकर अपील आयुक्त जिसे पटसन सर्किल कलकत्ता में सहायक आयकर निरीक्षण आयुक्त के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है।	सहायक आयकर अपील आयुक्त जिसे स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट आ० अ० के विनिश्चय के खिलाफ अपील सुनने की शक्तियों से विनिहित किया गया है"	आयकर आयुक्त पश्चिम बंगाल-8, कलकत्ता

यह अधिसूचना पहली जून, 1978 से प्रभावी होगी।

[सं० 2322/एफ०सं० 188/4/78-आई टी (ए-1)]

(Central Board of direct Taxes)

New Delhi, the 27th May, 1978

INCOME-TAX

S.O. 3504.—In exercise of the powers conferred by Section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and of all the powers enabling it in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following addition to the Schedule annexed to its Notification No. 1 (F. No. 55/233/63-IT) dated 18-5-1964 as amended from time to time.

In the said Schedule after S. No. 86, the following shall be added :—

SCHEDULE

Sl. No.	Persons	I.T.O.	I.A.C.	A.A.C.	C.I.T.
1	2	3	4	5	5
'87.	All manufacturers of Jute Goods, All dealers in Jute Goods, All dealers in raw Jute, All brokers in Jute goods, and All brokers in raw jute having their places of business in the city of Calcutta and the civil Disiricts of 24-Paraganas and Howrah but excluding the persons or classes of persons or cases or classes of cases falling in the same categories that have been specifically assigned and which may be assigned in future to the following Income-tax Circles/Districts in Calcutta : (i) Central Circles, Calcutta, (ii) District V(2), Calcutta (shortly to be re-designated as Special Investigation Circle-III, Calcutta) and (iii) Foreign Companies Circles-I & II Calcutta.	All I.T.Os in Jute Circle, Calcutta (A to F Wards).	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, who has been appointed to perform the functions of an Inspecting Assistant Commissioner of Incmae-tax in respect of Jute Circle, Calcutta.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, who has been invested with powers to hear appeals against the decision of the ITO/ITOs referred to in Col. 3.	Commissioner of Income-tax, Weest Bengal-V, Calcutta.

This notification will have effect from 1st June, 1978"

[No. 2322/F. No. 188/4/78-IT(AI)]

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1978

आय-कर

का० आ० 3505.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष करबोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० 1090 (फा० सं० 187/2/74-आ० क० (ए० 1) तारीख 20-9-1975 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

क्रम सं० 15 के सामने स्तंभ 1, 2 और 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

आयकर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3
15. मध्य प्रदेश	भोपाल	1. ए० बी० सी०, अतिरिक्त सी० और एफ० वार्ड भोपाल 2. वेतन सर्किल 3. सर्वेक्षण सर्किल 4. बेतूल 5. भिण्ड 6. दतिया 7. देवास 8. धार 9. ग्वालियर 10 गुना 11. होशंगाबाद 12. इन्दौर 13. खण्डवा 14. खारगांव 15. मन्दसौर 16. मोरैना 17. रायसेन 18. राजगढ़ 19. रतलाम 20. सेहोर 21. शाजापुर 22. शिवपुरी 23. उज्जैन 24. विदिशा 25. झबुआ

यह अधिसूचना 1-8-78 से प्रभावी होगी।

[सं० 2426/फा० सं० 187/17/78-आ० क० (ए1)]

New Delhi, the 19th July, 1978

INCOME-TAX

S.O. 3505.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Notification No. 1090 (F. No. 187/2/74-IT (AI) dated 20-9-1975, as amended from time to time.

The entries under columns 1, 2 and 3 against Sl. No. 15 shall be substituted by the following entries.

Commissioner of Income Tax	Head Quarters	Jurisdiction
1	2	3
15. Madhya Pradesh-I	Bhopal	1. A, B, C, Additional C & F Wards Bhopal. 2. Salary Circle. 3. Survey Circle. 4. Betul. 5. Bhind. 6. Datia. 7. Dewas. 8. Dhar. 9. Gwalior. 10. Guna. 11. Hoshangabad. 12. Indore. 13. Khandwa. 14. Khargone. 15. Mandsaur. 16. Morena. 17. Raisen. 18. Rajgarh. 19. Ratlam. 20. Sehore. 21. Shajapur. 22. Shivpuri. 23. Ujjain. 24. Vidisha. 25. Zabua.

This notification shall take effect from 1-8-78.

[No. 2426/F. No. 187/17/78-IT(AI)]

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1978

आय-कर

का० आ० 3506.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1971 की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी अधिसूचना सं० 1948 (फा० सं० 188/4/77-आई टी (ए 1) तारीख 1-9-1977 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में क्रम सं० 84 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

1	2	3	4	5	6
84(i)	ऐसे सभी व्यक्ति, जिनकी बाबत अतिरिक्त सुरक्षा अधिनियम के अधीन और/या विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन तस्करी संबंधी कार्यों और विदेशी मुद्रा की धोखा-धड़ी के लिए विरुद्ध करने का आदेश किया गया है और जो उक्त अधिनियमों के अधीन आदेश	आय-कर अधिकारी केन्द्रीय सर्किल-1 अहमदाबाद	स० आ० आ० क० केन्द्रीय रेंज-1, अहमदाबाद जिस की अधिकारिता स्तम्भ 3 में उल्लिखित सर्किल पर है।	स० आ० आ० अहमदाबाद, रेंज-1, अहमदाबाद जिस की अधिकारिता स्तंभ 3 में उल्लिखित सर्किल पर है।	आय-कर आयुक्त, गुजरात-1, जिसकी अधिकारिता स्तंभ 3 में उल्लिखित सर्किल पर है।

1	2	3	4	5	6
	पारित होने से पूर्व गुजरात राज्य में अहमदाबाद, गांधीनगर, कैरा, मेहसाना, बनासकांठा के राजस्व जिलों के भीतर निवास कर रहे थे या कारबार या व्यवसाय करते थे और जिनके मामले आय-कर अधिनियम की धारा 127 के अधीन केन्द्रीय सर्किल अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, भावनगर, बड़ौदा और सूरत के किसी आय-कर अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं ।				
(ii)	ऐसे सभी व्यक्ति, जिनकी बाबत आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन और /या विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी संबंधी कार्यों और विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी के लिए उन्हें निरुद्ध करने का आदेश किया गया है और जो उक्त अधिनियमों के अधीन आदेश पारित होने से पूर्व गुजरात राज्य में पंचमहल, बड़ौदा, बड़ौच, सूरत, डांगा और वलसर के राजस्व जिलों और दमण, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे थे या कारबार या व्यवसाय करते थे और जिनके मामले आय-कर अधिनियम की धारा 127 के अधीन केन्द्रीय सर्किल अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, भावनगर, बड़ौदा और सूरत के किसी आय-कर अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं ।	आयकर-अधिकारी, केन्द्रीय सर्किल I सूरत	सा० आ० क० आ० केन्द्रीय रेंज, बड़ौदा जिसकी अधिकारिता स्तंभ 3 में उल्लिखित सर्किल पर है।	स० आ० आ० सूरत रेंज, सूरत जिसकी अधिकारिता स्तम्भ 3 में उल्लिखित सर्किल पर है।	आय-कर आयुक्त गुजरात, जिन की अधिकारिता स्तम्भ 3 में उल्लिखित सर्किल पर है।
(iii)	ऐसे सभी व्यक्ति, जिनकी बाबात आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन और या विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन तस्करी संबंधी कार्यों और विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी के लिए उन्हें निरुद्ध करने का आदेश किया गया है और जो उक्त अधिनियमों के अधीन आदेश पारित होने से पूर्व गुजरात राज्य में राजकोट, जूनागढ़, सुरेन्द्रनगर, भावनगर, अमरेली, जामनगर और कच्छ और दीव संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व जिलों के भीतर निवास कर रहे थे या कारबार या व्यवसाय करते थे और जिनके मामले आय-कर अधिनियम की धारा 127 के अधीन केन्द्रीय सर्किल अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, भावनगर, बड़ौदा और सूरत के किसी आयकर अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं ।	आय-कर अधिकारी, केन्द्रीय सर्किल जामनगर ।	स० आ० आ० केन्द्रीय रेंज-II अहमदाबाद जिसकी अधिकारिता स्तंभ 3 में उल्लिखित सर्किल पर है ।	स० आ० अ०, जामनगर जिसकी अधिकारिता स्तम्भ 3 में उल्लिखित सर्किल पर है।	आय-कर आयुक्त, गुजरात केन्द्रीय, अमहदाबाद जिसकी अधिकारिता स्तंभ 3 में उल्लिखित सर्किल पर है ।

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1978 से प्रवृत्त होगी ।

[सं० 2448/फा० सं० 188/8/78-आई० टी० (ए० 1)]

New Delhi, the 31st July, 1978

INCOME-TAX

S.O. 3506.—In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax Act, 1961 the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the schedule annexed to its Notification No. 1948 (F. No. 188/4/77-IT AI) dated 1-9-1977.

In the said Schedule at Sr. No. 84 the following shall be substituted.

1	2	3	4	5	6
84	(i) All persons in respect of whom a.. order of detention has been made under the Maintenance of Internal Security Act (for Smuggling Activties and foreign exchange recketeering) and/or Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and who prior to passing of order under the said Acts	ITO Central Cir. I, A'bad.	IAC Central Range-I, A'bad who has jurisdiction over the Circle mentioned in Col. 3.	AACARI A'bad who has jurisdiction over the Circle mentioned in Col. 3.	C.I.T., Gujarat Central Ahmedabad who has jurisdiction over the Circle mentioned in Col. 3.

1	2	3	4	5	6
	were residing or carrying on business or profession within the Revenue Districts of Ahmedabad, Gandhinagar, Kaira, Mehsana, Banaskantha and Sabarkantha of the State of Gujarat and whose cases are not assigned to any of the I.T.Os. in Central Circles, Ahmedabad, Rajkot Jamnagar, Bhavnagar, Baroda and Surat by an Order u/s. 127 of the I.T. Act.				
(ii)	All person in respect of whom an order of detention has been made under the Maintenance of Internal Security Act (for Smuggling activities and foreign exchange racketeering) and/or Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and who prior to passing of orders under the said Act were residing or carrying on business or profession within the Revenue Districts of Panchmahal, Baroda, Broach, Surat, Danga and Bulsar of the State of Gujarat and in the Union Territory of Daman, Dadra and Nagar Haveli and whose cases are not assigned to any of the I.T.Os. in Central Circles, Ahmedabad, Rajkot, Jamnagar, Bhavnagar, Baroda and Surat by an order under section 127 of the I.T.Act.	ITO, Cen. Cir. I, Surat.	IAC Cen. Range, Baroda who has jurisdiction over the circle mentioned in Col. 3.	AAC Surat Range Surat who has Jurisdiction over the circle mentioned in Col. 3.	CIT, Gujarat Central Ahmedabad who has jurisdiction over the circle mentioned in Col. 3.
(iii)	All persons in respect of whom an order of detention has been made under the Maintenance of Internal Security act (for Smuggling activities and foreign Exchange Racketeering) and/or Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and who prior to passing of orders under the said Acts were residing or carrying on business or profession within the Revenue Districts of Rajkot, Junagadh, Surendranagar, Bhavnagar, Amreli, Jamnagar and Kutch of the State of Gujarat and in the Union Territory of Diu and whose cases are not assigned to any of the ITOs in Central Circles, Ahmedabad, Rajkot, Jamnagar, Bhavnagar, Baroda, and Surat, by an order u/s. 127 of the Income-tax Act.	I.T.O. Central, Circle, Jamnagar.	I.A.C. Central Range-II, Ahmedabad who has jurisdiction over the Circle mentioned in Col. 3.	A.A.C. Jamnagar Range, Jamnagar who has jurisdiction over the Cir. mentioned in Col. 3.	CIT, Gujarat Central Ahmedabad who has got jurisdiction over the Circle mentioned in Col. 3.

2. This notification shall have effect from Ist August, 1978.

[No. 2448/F. No. 188/5-78-IT—(AI)]

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1978

आय-कर

का० आ० 3507.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 679 (फा० सं० 187/2/74-आ० क० (ए1) तारीख 20 जुलाई, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करता है :

क्रम सं० 10-ङ पर स्तंभ 3 के नीचे की विद्यमान मद सं० 3 निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाएगी।

केन्द्रीय सर्किल 1, 2 और 3 सूरत

यह अधिसूचना 1-9-78 से प्रभावी होगी।

[सं० 2485 फा० सं० 187/21/78-आ०क० (ए-I)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

New Delhi, the 24th August, 1978

(INCOME-TAX)

S.O. 3507.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following amendments to its Notification No. 679 (F. No. 187/2/74-IT(AI) dated 20th July, 1974 as amended from time to time.

Existing item No 3 under column 3 at Sr. No. 10-E shall be read as follows :—

Central Circles I, II and III, Surat.

This notification will take effect from 1-9-78.

[No. 2485/F. No. 187/21/78-IT(AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

वार्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1978

शुद्धि-पत्र

का०आ० 3508.—3 जून, 1978 के भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3(II) में पृष्ठ 1478 पर प्रकाशित वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की 16 मई, 1978 की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1691 (संख्या एफ० 8-9/78-ए० सी०) के हिन्दी पाठ में गांव पोरखेड़ी के सामने "4.504" हेक्टेयर के स्थान पर "4.505" हेक्टेयर प्रतिस्थापित कर लिया जाय।

[सं० एफ० 8-9/78-ए० सी०]

एम० पी० वर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1978

का०आ० 3509.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (I) और (II) के उपबन्ध, 9 जनवरी, 1980 तक की अवधि के लिए यूनियन बैंक आफ इण्डिया तथा इण्डियन बैंक पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक कि उक्त उपबन्ध, इन बैंकों के अध्यक्षों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के, भारतीय निर्यात ऋण एवं गारन्टी निगम लि० के निदेशक बनने पर रोक लगाते हैं क्योंकि यह कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है।

[संख्या एफ० 15(39)-बी०ओ० III/77]

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

(Banking Division)

New Delhi, the 21st November, 1976

S.O. 3509.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the B R Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-clauses (i) & (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply upto 9th January 1980 to the Union Bank of India and Indian Bank in so far as the said provisions prohibit their Chairmen and the Chief Executive Officers from being directors of the Export Credit & Guarantee Corporations of India Ltd., being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

[No. 15(39)-B.O.III/77]

का०आ० 3510.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया पर 19 अगस्त, 1979 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक वे मैसर्स इण्डिया लेदर कारपोरेशन (प्रा०) लि० और मैसर्स क्रीम लेदर कम्पनी लिमिटेड के शेयरों की इस बैंक धारिता से सम्बन्धित हैं।

[संख्या 15(14)-बी० ओ० III/78]

S.O. 3510.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India hereby declares that the provisions of Sub-setcion (2) of Section 19 of the said Act shall not apply to the Central Bank of India upto 19th August 1979 in so far as they relate to its holding in the shares of M/s. India Leather Corporation (P) Ltd., and M/s. Chrome Leather Co. Ltd.

[No. 15(14)-B.O.III/78]

का०आ० 3511.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता पर 25 अक्तूबर, 1979 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उनका सम्बन्ध इसकी, यूनाइटेड इण्डस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता की शेयर धारिता से है।

[संख्या 15(23)-बी० ओ० III/78]

S.O. 3511.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of Section 19 of the said Act shall not apply till the 25th October, 1979, to the United Bank of India, Calcutta in so far as they relate to its holding of the shares in the United Industrial Bank Ltd., Calcutta.

[No. 15(23)-B.O.III/78]

का०आ० 3512.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 108 की उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड पर 31 मार्च, 1979 तक अथवा इस बैंक के अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति तक, इसमें जो भी पहले हो, तब तक लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15(22)-बी० ओ० III/78]

मे० भा० उसगावकर, अवर सचिव

S.O. 3512.—In exercise of powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of Section 10B of the said Act, shall not apply to Lakshmi Vilas Bank Ltd., till the 31st March 1979 or till the appointment of the next whole-time Chairman of that Bank, whichever is earlier.

[No. 15(22)-B.O.III/78]
M. B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1978

का० आ० 3513—निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारन्टी निगम अधिनियम 1961 (1961 का 47) की धारा 6 की उपधारा 1 के खंड (ङ) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारन्टी निगम के निदेशक मण्डल में निम्नलिखित व्यक्तियों को 23 नवम्बर, 1978 से दो वर्ष की अवधि के लिये निदेशक के रूप में नियुक्त करती है ।

(1) श्री वी० एस० नटराजन,
प्रबन्ध निदेशक,
भारतीय स्टेट बैंक,
एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग,
केन्द्रीय कार्यालय,
बम्बई-400 021

(2) श्री पी० एफ० गट्टा,
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक,
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया,
सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, "चन्द्रमुखी"
बम्बई-400021

(3) श्री ए० घोष,
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक,
इलाहाबाद बैंक,
14, इंडिया एक्सचेंज प्लेस,
कलकत्ता-700001

[संख्या एफ० 6/7/78-बी० ओ०-I]
च० ना० मीरचन्दानी, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd November, 1978

S.O. 3513.—In pursuance of the provision sof clause (c) of of sub-section (1) of section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961), the Central Government hereby nominates the following persons as directors to the Board of directors of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation for a period of two years with effect from 23rd November, 1978.

(1) Shri V. S. Natarajan,
Managing Director,
State Bank of India,
Administrative Building,
Madam Cama Road, Central Office,
Bombay-400021.

(2) Shri P. F. Gutta,
Chairman and Managing Director,
Central Bank of India,
Central Bank Building,
"Chandermukhi",
Nariman Point,
Bombay-400021.

(3) Shri A. Ghosh,
Chairman and Managing Director,
Allahabad Bank,
14, India Exchange Place,
Calcutta-700001.

[No. F. 6/7/78-BO. I]
C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1978

का० आ० 3514—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 की उपधारा (क) के साथ पठित खण्ड 8 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री एम० एन० गोईपोरिया को 27 नवम्बर, 1978 से शुरू होकर 26 नवम्बर, 1981 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए देना बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 9/24/78 बी० ओ० (I)]

New Delhi, the 25th November, 1978

S.O. 3514.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri M. N. Goiporia as the Managing Director of the Dena Bank for a term of three years commencing on 27th November, 1978 and ending with 26th November, 1981.

[No. F. 9/24/78-BO. I (1)]

का० आ० 3515—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 5 की उपधारा (1) के साथ पठित खण्ड 7 के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एम० एन० गोईपोरिया जिन्हें 27 नवम्बर, 1978 से देना बैंक का प्रबन्धक निदेशक नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से देना बैंक के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

[संख्या एफ० 9/24/78-बी ओ० 1(2)]
बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. .—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India hereby appoints Shri M. N. Goiporia who has been appointed as the Managing Director of the Dena Bank with effect from 27th November, 1978 to be the Chairman of the Board of Directors of the Dena Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/24/78-BO. I (2)]
BALDEV SINGH, Jt. Secy.

New Delhi, the 16th November, 1978

ERRATA

S.O. 3516.—In the English version of the notification No. F. 8-3/77-AC, dated the 23rd December, 1977 and subsequent errata No. F. 8-3/77-AC dated the 23rd June, 1978, the name of Co-operative Bank, referred to therein, may be read as "Savarkundla Nagrik Sahakari Bank Ltd.".

[No. 8-3/77-AC]
M. P. VARMA, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1978

का०आ० 3517—भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3(ii) में प्रकाशनार्थ, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 29 सितम्बर, 1978 की अधिसूचना संख्या 8-9/78-ए० सी० में शब्द "रोड" से पहले "सभा जी राव" शब्द के स्थान पर "सया जी राव" शब्द प्रतिस्थापित समझा जाये।

[संख्या 8-9/78-ए० सी०]
एम०पी० वर्मा, अवर सचिव

भारतीय रिजर्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

का०आ० 3518—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में 1978 के दिनांक 6 अक्तूबर, को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा :—

S. O. 3518.—An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 6th day of October, 1978 :—

इशु विभाग

ISSUE DEPARTMENT

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	16,14,35,000		सोने का सिक्का और बुलियन Gold Coin and Bullion		
संचलन में नोट Notes in circulation	9212,57,04,000		(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	214,21,78,000	
जारी किये गये कुल नोट Total Notes issued		9228,71,39,000	(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India		
			विदेशी प्रतिभूतियां Foreign Securities	2295,32,65,000	
			जोड़ Total		2509,54,43,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin		33,99,08,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां Government of India Rupee Securities		6685,17,88,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial papers		
कुल देयताएं Total Liabilities		9228,71,39,000	कुल आस्तियां Total Assets		9228,71,39,000

दिनांक : 12 अक्तूबर, 1978
Dated the, 12th day of October, 1978

के० एस० कृष्णस्वामी, उप-गवर्नर
K. S. KRISHNASWAMY, Dy. Governor.

6 अक्टूबर, 1978 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

Statement of the affairs of the Reserve Bank of India, banking Department as on the 6th October, 1978

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.
चुकता पूंजी Capital Paid Up	5,00,00,000	नोट Notes	16,14,35,000
आरक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	2,96,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि) National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	610,00,00,000	छोटा सिक्का Smalls Coin	5,84,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilization) Fund	195,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल Bills Purchased and Discounted:—	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	915,00,00,000	(क) देशी (a) Internal	50.89,94,000
जमा राशियां :— Deposits :—		(ख) विदेशी (b) External	..
(क) सरकारी (a) Government :		(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	1771,18,72,000
(i) केन्द्रीय सरकार (i) Central Government	1267,70,79,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया* Balances Held Abroad*	1642,48,14,000
(ii) राज्य सरकारें (ii) State Governments	14,81,62,000	निवेश** Investments**	880,69,16,000
(ख) बैंक (b) Banks :		ऋण और अग्रिम :— Loans and Advances to :	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक (i) Scheduled Commercial Banks	2033,48,16,000	(i) केन्द्रीय सरकार को (i) Central Government	..
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (ii) Scheduled State Co-operative Banks	29,95,38,000	(ii) राज्य सरकारों को@ (ii) State Governments@	75,20,14 000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	2,36,20,000	ऋण और अग्रिम Loans and Advances to :—	
(iv) अन्य बैंक (iv) Other Banks	1,78,91,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को† (i) Scheduled Commercial Banks†	251,19,16,000
(ग) अन्य (c) Others	1532,75,56,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	380.85,73,000
देय बिल Bills Payable	180,72,61,000	(iii) दूसरों को (iii) Others	4,75,00 000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश : Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund :	
		(क) ऋण और अग्रिम (a) Loans and Advances to:—	
		(i) राज्य सरकारों को (i) State Governments	110,82,46,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	16,65,48,000
		(ii) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक को (iii) Central Land Mortgage Banks	..

*नकदी, सावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं ।

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घ कालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घ कालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं ।

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Opeations) Fund.

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं ।

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but Including temporary overdrafts to State Governments.

†भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 2,76,00,000 रुपये शामिल हैं ।

†Includes Rs. 2,76,00,000 advanced to Scheduled Commerical banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं ।

‡Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilization) Fund.

देयताएं Liabilities	रु० Rs.		आस्तियां Assets	रु० Rs.	
अन्य देयताएं Other Liabilities		439,60,000	(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को (iv) Agricultural Refinance and Development Corporation		215,60,00,000
			(ख) केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures		7,67,64,000
			राष्ट्रीय कृषि ऋण, (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund		
			राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम Loans and Advances to State Co-operative Banks		132,48,57,000
			राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund		
			(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम (a) Loans and Advances to the Development Bank		708,85,68,000
			(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए बाण्डों/डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank		..
			अन्य आस्तियां Other Assets		1237,39,86,000
रुपये Rupees		7502,98,83,000	रुपये Rupees		7502,98,83,000

के०एस० कृष्णास्वामी, उप गवर्नर
K. S. KRISHNASWAMY, Dy. Governor

दिनांक 12 अक्तूबर 1978
Dated the 12th day of October, 1978

[No. F. 10/1/78-BOI]

का०आ० 3519.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में 1978 के दिनांक 13 अक्तूबर को प्राप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा।

S.O. 1519.—An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934 for the week ended the 13th day of October, 1978

निर्गम विभाग
Issue Department

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	52,07,16,000		सोने का सिक्का और बुलियन :— Gold Coin and Bullion		
संचलन में नोट Notes in circulation	9376,00,12,000		(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	214,21,73,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां Foreign Securities	2295,32,65,000	
जारी किये गये कुल नोट Total Notes issued		9428,07,28,000	जोड़ Total		2509,54,43,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin		33,35,70,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां Government of India Rupee Securities		6885,19,15,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper		
कुल देयताएं Total Liabilities		9428,07,28,000	कुल आस्तियां Total Assets		9428,07,28,000

दिनांक : 18 अक्तूबर, 1978
Dated the 18th day of October, 1978

आई जी पटेल, गवर्नर
I. G. Patel, Governor

13 अक्तूबर 1978 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 13th October, 1978.

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.
चुकता पूंजी Capital Paid Up	5,00,00,000	नोट Notes	52,07,16,000
आरक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	1,71,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	610,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	6,11,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	195,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल Bills Purchased and Discounted :—	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि) National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund	915,00,00,000	(क) देशी (a) Internal	50,89,83,000
जमा राशियां : Deposits :		(ख) विदेशी (b) External	—
(क) सरकारी (a) Government		(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	1727,26,15,000
केन्द्रीय सरकार (i) Central Government	1372,23,56,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया Balances Held Abroad*	1641,06,40,000
राज्य सरकारें (ii) State Governments	14,94,98,000	निवेश Investments**	994,42,02,000
(ख) बैंक (b) Banks		ऋण और अग्रिम :— Loans and Advances to :—	
अनुसूचित वाणिज्य बैंक (i) Scheduled Commercial Banks	2024,96,27,000	केन्द्रीय सरकार को (i) Central Government	—
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (ii) Scheduled State Co-operative Banks	29,60,81,000	राज्य सरकारों को (ii) State Governments@	26,00,00,000
गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	2,43,32,000	ऋण और अग्रिम:— Loans and Advances to :	
अन्य बैंक (iv) Other Banks	1,80,60,000	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (i) Scheduled Commercial Banks	260,52,47,000
(ग) अन्य (c) Others	1520,56,58,000	राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	388,95,46,000
देय बिल Bill Payable	187,75,03,000	दूसरों को (iii) Others	79,00,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) ऋण और अग्रिम (a) Loans and advances to :— राज्य सरकारों को (i) State Governments	110,82,46,000

* नकदी, सावधिक जमा और अल्पकालिक प्रतिभूतियां शामिल हैं।

* Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

** राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीक प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@ राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund.

† भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 2,76,00,000 रुपये शामिल हैं।

† Includes Rs. 2.76,00,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

‡ राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

‡ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

देयताएं Liabilities	रु० Rs.	आस्तियां Assets	रु० Rs.
अन्य देयताएं Other Liabilities	568,43,93,000	राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	16,53,99,000
		केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों को (iii) Central Land Mortgage Banks	
		कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को (iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	215,60,00,000
		(ख) केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	7,67,64,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम Loans and Advances to State Co-operative Banks	132,48,24,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम (a) Loans and Advances to the Development Bank	721,36,48,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	—
		अन्य आस्तियां Other Assets	1251,19,96,000
रुपये Rupees	7597,75,08,000	रुपये Rupees	7597,75,08,000

I. G. Patel, *Governor*,

[No. F. 10/1/78-BOI)

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

दिनांक 18 अक्तूबर, 1978

Dated the 18th day of October, 1978

सीमा तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता का कार्यालय, बंगलोर

बंगलौर, 5 अक्तूबर, 1978

सीमा-शुल्क

का० आ० 3520.—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की तारीख 18 जुलाई, 1975 की अधिसूचना संख्या 79/सीमा-शुल्क फा० सं० 473/2/75 सीमा-शुल्क-VII द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर० एन० शुक्ला, समाहर्ता सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बंगलौर, कर्नाटक समाहर्तालय, एतद्द्वारा कर्नाटक राज्य के धारवाड जिले के रानेबेन्नूर तालुक का 'करूर ग्राम' को 'भांडागार केन्द्र' घोषित करता हूं ।

[अधिसूचना संख्या 4/78/सी०सं० VIII 40/2/78सी०शु०]

आर० एन० शुक्ला, समाहर्ता

Office of the Collector of Central Excise, Bangalore

Bangalore, the 5th October, 1978

CUSTOMS

S.O. 3520.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), read with Notification No. 79/Customs/F. No. 473/2/75 Cus. VII dated 18-7-1975 of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue). I, R. N. Shukla, Collector of Customs and Central Excise, Bangalore, Karnataka Collectorate hereby declare "Karur Village" of Ranebennur Taluk, Dharwar District, in the State Karnataka, to be warehousing station.

[Notification No. 4/78/C. No. VIII/40/2/78 Cus.]

R. N. SHUKLA, Collector

वाणिज्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1978

का०आ० 3521.—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव, श्री ए० एस० सेठी को 28 अक्तूबर, 1978 के दोपहर के पहले से आगे और आदेश होने तक के लिए उनके वर्तमान कार्यभार के साथ-साथ बायदा बाजार आयोग, बम्बई का सदस्य नियुक्त करती है तथा उक्त आयोग का अध्यक्ष भी नामित करती है ।

[मिसिल सं० ए० 24011/3/78-प्रशा० I]

एम० एल० जाटव, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Civil Supplies and Co-operation)

New Delhi, the 3rd November, 1978

S.O. 3521.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 3 of Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri A. S. Sethi, Joint Secretary to the Government of India in the Department of Civil Supplies and Co-operation as a Member of the Forward Markets Commission, Bombay, and also nominates him to be the Chairman of that Commission with effect from the afternoon of 28th October, 1978 in addition to his present duties till further orders.

[File No. A-24011/3/78-Estt. I]

M. L. JATAV, Under Secy.

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1978

का०आ० 3522.—राष्ट्रपति, ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया, नई दिल्ली के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 59 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् के अध्यक्ष श्री एम० एम० अनवरुल्ला को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया के अवैतनिक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

[सं० 17/78 (1/1/78-टी० एफ०)]

(Department of Commerce)

New Delhi, the 10th November, 1978

S.O. 3522.—In exercise of the powers conferred under Article 59(2) of the Articles of Association of the Trade Fair Authority of India, New Delhi, the President is pleased to appoint Shri M. M. Anwarulla, Chairman of the Leather Export Promotion Council as part time Director of the Trade Fair Authority of India with effect from the date of issue.

[No. 17/78(1/1/78-IF)]

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1978

का०आ० 3523.—राष्ट्रपति, ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया के संगम अनुच्छेद 59(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अध्यक्ष से परामर्श करके, श्री एन० के० भारद्वाज को 7 नवम्बर, 1978 के पूर्वाह्न से ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया के निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं । राष्ट्रपति, अध्यक्ष से परामर्श करके तथा ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 59(7) के अधीन श्री एन० के० भारद्वाज को उपर्युक्त तारीख से प्रबन्ध निदेशक के रूप में भी नियुक्त करते हैं ।

[सं० 16/78 (1/1/78-टी० एफ०)]

एम० पी० श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 13th November, 1978

S.O. 3523.—In exercise of the powers conferred under Articles 59(2) of Article of Association of the Trade Fair Authority of India and in consultation with the Chairman, the President is pleased to appoint Shri N.K. Bhardwaj as Director of the Trade Fair Authority of India with effect from the afternoon of 7th November, 1978 in consultation with the Chairman and under Article 59(7) of the Articles of Association of the Trade Fair Authority of India, the President is further pleased to appoint Shri N.K. Bhardwaj as Managing Director with effect from the aforesaid date.

[No. 16/78 (1/1/78-TF)]

M. P. SRIVASTAVA, Under Secy.

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1978

का०आ० 3524.—सर्वश्री हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० पिंजौर जिला अम्बाला को सी०एस०एस०आर०से लाइसेंस के लिए संलग्न सूची

के अनुसार पूंजीगत माल के आयात के लिए 12,20,000/- रुपये का एक आयात लाइसेंस सं० आई/सी जी/2033241 दिनांक 9-12-77 प्रदान किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है ।

आगे यह भी बताया गया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति बिल्कुल उपयोग में नहीं लाई गई है और इसमें 12,20,000/- रुपये की धनराशि शेष थी ।

इस तर्क के समर्थन में, आवेदक ने चण्डीगढ़ के प्रथम श्रेणी के जिलाधीश के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । तद्नुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति खोई गई है । इसलिए, यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उपधारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिंजौर को जारी किए गए लाइसेंस सं० आई/सी जी/2033241 दिनांक 9-12-77 की उक्त मूल मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[सं० सी जी 2/एच आई (66-68)/77-78/1537)]

राजिन्दर सिंह, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

ORDER

New Delhi, the 23rd November, 1978

S.O. 3524.—M/s. Hindustan Machine Tools Ltd., Pinjore, Dt. Ambala were gratned an import licence No. 1/CG/2033241 dated 9-12-77 for Rs. 12,20,000/- for the import of Capital Goods as per list attached from C.S.S.R. They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control Copy of the said licence on the ground that the original exchange control copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original exchange control copy has not been utilized at all and the balance available on it was Rs. 12,20,000.

In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn in before Magistrate First Class, Chandigarh. I am accordingly satisfied that the original exchange control copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub Clause 9(00) of the import (control) Order, 1955 dated 7-12-55 as amended, the said original exchange control copy of the licence No. 1/CG/2033241 dated 9-12-77 issued to M/s. Hindustan Machine Tools, Pinjore is hereby cancelled.

The duplicate copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. CGII/HT (66-68)/77-78/1537]

RAJINDER SINGH, Dy. Chief Controller

for Chief Controller of Imports and Exports.

(नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली 1978-11-22

भारतीय मानक संस्था

का० आ० 3225.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-6719 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं 1978-03-01 से IS : 1027-1968 के निरस्त हो जाने के कारण रद्द कर दिया गया है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस सं० और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
1	2	3	4	5
1.	सी एम/एल-6719 1978-01-29	दि इंडियन केबल कं० लि०, 9, हेयरस्ट्रीट कलकत्ता-700001 (पं० बंगाल)	खानों में प्रयुक्त कागज रोधित केबल-मार्का- "इंकैब"	IS : 1027-1968 खानों में प्रयुक्त कागज रोधित केबल—

[सं० सी एम डी/55:6719]

ए० बी० राव, उप महानिदेशक

(Department of Civil Supplies and Co-operation)

(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 1978-11-12

S.O. 3525.—Inpursnce of sub-regulation (4)of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No.CM/L-6719 particulars of which are given below has/have been cancelled with effect from 1978-03-01 due to withdrawal of IS : 1027-1968.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-6719 1978-01-29	The Indian Cable Co. Ltd., 9, Hare Street, Calcutta-700001 (W. Bengal).	Paper insulated cables for use in mines Brand : 'INCAB'	IS : 0127-1968 Paper insulated cables for use in mines.

[No. CMD/55 : 6719

A.B. RAO, Dy. Director General.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1978

का०आ० 3526.—कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45वां) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा औद्योगिक विकास विभाग में आयुक्त (औ० सह०) श्री के० पी० परमेश्वरन को 23 नवम्बर, 1978 से अग्रे आदेशों तक कयर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

[सं० 15/70/78–आई० सी० सी०]

बी० आर० आर० आयंगर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRIAL

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 23rd November, 1978

S.O.3526.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), the Central Government hereby appoints Shri K.P. Parameshwaran, Commissioner (IC), Department of Industrial Development as Chairman, Coir Board, with effect from 23rd November, 1978 until further orders.

]No. 15/70/78-ICC[

B.R.R. IYENGAR, Joint Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th November, 1978

S.O.3527.—In the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 620(E), dated the 28th October, 1978, published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 28th October, 1978, on page 1362——

in paragraph 1, of English version, in the fifth line, for "18EB" read "18 FB".

[F. No. 22/19/78-Jute]

S. DAVE, Under Secy.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1978

का०आ० 2528.—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के लिये गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक और गुजरात राज्य में विरमगाम से गुजरात शोधनशाला कोयली तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है ।

और यतः इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को अनुसूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखायी गयी तिथि से पर्यवसित कर दिया है ।

अब अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 1963 के नियम 4 के अधीन, सक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

व्यधन क्षेत्र सलाया से मथुरा के पाइपलाइन संक्रिया पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	संक्रिया पर्यवसान की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	हेबतपुर	960	29-3-1975	5-4-1978

[सं० 12020/1/78-प्रो०]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILISERS

(Petroleum Department)

New Delhi, the 13th November, 1978

S. O. 3528.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of Section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujrat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura

Name of Ministry	Name of village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of Termination
Petroleum, Chemicals & Fertilisers (Petroleum Department)	Hebatpur	960	29-3-1975	5-4-1978

[No. 12020/1/78 Prod.]

का० आ० 3529.—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के लिये गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक और गुजरात राज्य में विरमगाम से गुजरात शोधनशाला कोयली तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है ।

और यतः इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट प्रक्रिया की अनुसूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखायी गयी तिथि से पर्यवसित कर दिया है ।

अब अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम के अधीन, सक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

व्यधन क्षेत्र सलाया से मथुरा के पाइपलाइन संक्रिया पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	संक्रिया पर्यवसान की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	बजरंगपुरा	1391	3-5-1975	15-5-1978
	वणा	,,	,,	12-5-1978
	लखतर	,,	,,	29-5-1978
	नागडकापाटी (लखतर)	,,	,,	29-5-1978
	सदाद	,,	,,	8-5-1978
	आवलसर	,,	,,	8-5-1978
	केसरीया	,,	,,	23-4-1978
	लीलापुर	,,	,,	26-5-1978
	धंकी	,,	,,	21-4-1978
	छारव	,,	,,	12-4-1978
	भास्करपरा	,,	,,	9-4-1978
	ज्योतिपुरा	,,	,,	23-4-1978
	विठलगरु	,,	,,	8-4-1978
	बाबाजीपरा	,,	,,	8-4-1978

[सं० 12020/1/78–प्रो० II]

S. O. 3529.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of Section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura

Name of Ministry	Name of village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of Termination
Petroleum, Chemicals & Fertilisers (Petroleum Department)	Bajrangpura	1391	3-5-1975	15-5-1978
	Vana	1391	3-5-1975	12-5-1978
	Lakhtar	1391	3-5-1975	29-5-1978
	Nagadkapati (Lakhtar)	1391	3-5-1975	29-5-1978
	Sadad	1391	3-5-1975	8-5-1978
	Adalsar	1391	3-5-1975	8-5-1968
	Kesaria	1391	3-5-1975	23-4-1978
	Lilapur	1391	3-5-1975	26-5-1978
	Dhanki	1391	3-5-1975	21-4-1978
	Olak	1391	3-5-1975	14-4-1978
	Chharad	1391	3-5-1975	12-4-1978
	Bhaskarpara	1391	3-5-1975	9-4-1978
	Jyotipura	1391	3-5-1975	23-4-1978
	Vitthalgadh	1391	3-5-1975	8-4-1978
	Babajipara	1391	3-5-1975	8-4-1978

[No. 12020/1/78 Prod. II]

का०आ० 3530.—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के लिये गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक और गुजरात राज्य में विरमगाम से गुजरात शोधनशाला कोयली तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है ।

और यतः इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को अनुसूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखायी गयी तिथि से पर्यवसित कर दिया है ।

अब अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन, सक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

व्यधन क्षेत्र सलाया से मथुरा पाइपलाइन संक्रिया पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	संक्रिया पर्यवसान की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) . . .	दावड़ा	1756	7-6-1975	1-10-1977

[सं० 12020/1/78-प्रो० III]

S.O. 3530.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of Section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Right of Use has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura

Name of Ministry	Name of village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of Termination
Petroleum, Chemicals & Fertilisers (Petroleum Department)	Davda	1756	7-6-1975	1-10-1977

[No. 12020/1/78 Prod. III]

का०आ० 3531.—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के लिए गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक और गुजरात राज्य में विरमगाम से गुजरात शोधनशाला कोयली तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है ।

और यतः इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को अनुसूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखायी गयी तिथि से पर्यवसित कर दिया है ।

अब अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन, सक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

व्यधन क्षेत्र सलाया से मथुरा पाइपलाइन संक्रिया पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	संक्रिया पर्यवसान की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) . . .	बाला	1923	21-6-1975	19-5-1978
	अणीद्रा	,,	,,	,,

[सं० 12020/1/78-प्रो० IV]

श्रीकान्त बड़ेरा, गुजरात राज्य के लिये अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

S.O. 3531.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of Section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in a clause (i) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura

Name of Ministry	Name of village	S. O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of Termination
Petroleum, Chemicals & Fertilisers (Petroleum Department)	Bala	1923	21-6-1975	19-5-1978
	Anindra	1923	21-6-1975	19-5-1978

[No. 12020/1/78 Prod-IV]

S. D. VADERA, Competent Authority Under the Act, for Gujarat State.

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1978

का०आ० 3532.—पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 611(ई) दिनांक 14 सितम्बर, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपर्युक्त अधिसूचना में नीचे दी गई अनुसूची में क्रम संख्या 2, कालम 3 में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि पढ़ी जाये, अर्थात् :—

"सम्पूर्ण गुजरात राज्य"

[सं० 12017/1/74—एल. एंड एल.—प्रो०]

New Delhi, the 6th July, 1978

S.O.3532.—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India, in the Ministry of Petroleum No. S. O. 611(E), dated the 14th September, 1976 namely :—

In the schedule below the said notification, against serial No. 2 in column 3 for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"The whole state of Gujarat".

[No. 12017/1/74-L &L/Prod.]

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1978

का०आ० 3533.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 1436 तारीख 20-5-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० में सभी संयंत्रों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील : बाली जिला : पाली राज्य : राजस्थान

ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	ऐयर	वर्गमीटर
कोट	216/1 मिस	0	00	81
	441	0	08	09

[क्रमांक 12020/2/78-प्रोड-I]

New Delhi, the 18th November, 1978.

S.O.3533.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum) S.O. 1436 dated 20-5-78 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of the power conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the India Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Bali	District:Pali	State: Rajasthan		
		Area		
Village	Khasra No.	H	A.	Sq. M
Kot	216/1 min	0	00	81
	441	0	08	09

(No. 12020|2|78 Prod I)

का० आ० 3534.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 1437 तारीख 20-5-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया है ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० में सभी संभारों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील : ब्यावर	जिला : अजमेर		राज्य : राजस्थान		
	खसरा नं०		क्षेत्रफल		
ग्राम	सांबिक	हाल	हैक्टर	ऐयर	वर्गमीटर
केसरपुरा	240 241	316	0	08	90

[क्रमांक 12020/2/78-प्रोड-II]

S.O.3534.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum) S.O. 1437 dated 20-5-78 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands spcified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of the power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the India Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Beawar	District : Ajmer		State : Rajasthan		
Village	Khasra No.		Area		
	Old	New	H.	A.	Sq. M.
Kesarpura	240 241	316	0	08	90

[No. 12020/2/78-Prod-II]

का० आ० 3535.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 1439 तारीख 20-5-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० में सभी संवंधों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील : देसूरी	जिला : पाली		राज्य : राजस्थान	
ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हैक्टर	ऐयर	वर्गमीटर
कोटड़ी	36	0	03	01
	38	0	14	63

[क्रमांक 12020/2/78—प्रौड IV]

S.O. 3535.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum) S.O. 1439 dated 20-5-78 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of the power conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Desuri	District : Pali		State : Rajasthan	
Village	Khasra No.	Area		
		H.	A.	Sq. M.
Kotari	36	0	03	01
	38	0	14	63

[No. 12020/2/78-Prod-IV]

का०आ० 3536.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 1438 तारीख 20-5-1978 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० में सभी संवंधों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनसूची

तहसील : देसूरी	जिला : पाली		राज्य : राजस्थान	
ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हैक्टर	ऐयर	वर्गमीटर
सिवास	129	0	06	35
	16	0	01	61

[क्रमांक 12020/2/78—प्रौड III]

S.O. 3536.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum) S.O. 1438 dated 20-5-1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1952) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of the power confered by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Desuri	District : Pali	State : Rajasthan		
Village	Khasra No.	Area		
		H.	A.	Sq. M.
Siwas	129	0	06	35
	16	0	01	61

[No. 12020/2/78-Prod-III]

का०आ० 3537.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1440 तारीख 20-5-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इंडियन आयल कारपोरेशन लि० में सभी भंयत्रों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील : रायपुर	जिला : पाली	राज्य : राजस्थान		
ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	ऐयर	वर्गमीटर
सैंदड़ा	128	0	15	81
	563	0	24	02
	513	0	11	33
	512	0	08	47
	510	0	03	79
	511	0	05	69
	528	0	03	79
	527	0	04	68
	405	0	00	38
	406	0	04	93
	407	0	02	02
	398	0	06	32

[क्रमांक 12020/2/78—प्रौड०-V]

S.O. 3537.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum) S.O. 1440 dated 20-5-1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of the power conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of his declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Raipur	District : Pali	State : Rajasthan		
Village	Khasra No.	Area		
		H.	A.	Sq. M.
Sondra	128	0	15	81
	563	0	24	02
	513	0	11	33
	512	0	08	47
	510	0	03	79
	511	0	05	69
	528	0	03	79
	527	0	04	68
	405	0	00	38
	406	0	04	93
	407	0	02	02
	398	0	06	32

[No. 12020/2/78-Prod-V]

का०आ० 3538.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1441 तारीख 20-5-1978 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित

करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इंडियन आयल कारपोरेशन लि० में सभी संपत्तियों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील : रायपुर	जिला : पाली		राज्य : राजस्थान	
ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हैक्टर	ऐयर	वर्गमीटर
सबलपुरा प्रथम	306	0	01	03
	305	0	00	53
	298	0	01	46
	296	0	02	92
	276	0	00	34
	254	0	01	46

[क्रमांक 12020/2/78-प्रौ०-VI]

S.O. 3538.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum) S.O. 1441 dated 20-5-1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore in exercise of the power confered by Subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of the power confered by Subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Raipur District : Pali State : Rajasthan

Village	Khasra No.	Area		
		H.	A.	Sq. M.
Sabalpura (I)	306	0	01	03
	305	0	00	53
	298	0	01	46
	296	0	02	92
	276	0	00	34
	254	0	01	46

[No. 12020/2/78-Prod. VI]

का०आ० 3539.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 1442 तारीख 20-5-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इंडियन आयल कारपोरेशन लि० में सभी संपत्तियों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील : आबूरोड	जिला : सिरोही		राज्य : राजस्थान	
ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हैक्टर	ऐयर	वर्गमीटर
सांतपुर	617	0	02	53
	618	0	05	06
	637	0	02	53

[क्रमांक 12020/2/78-प्रौ०-VII]

S. O. 3539.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum) S. O. 1442 dated 20-5-1978 uder Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Governent declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notificalon.

Now therefore in exercise of the power conferred by Subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of the power conferred by Subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Abu Road	District : Sirohi	State : Rajasthan		
Village	Khasra No.	Area		
		H.	A.	Sq. M.
Santpur	617	0	02	53
	618	0	05	06
	637	0	02	53

[No. 12020/2/78-Prod VII]

का० आ० 3540.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1443 तारीख 20-5-1978 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इंडियन आयल कारपोरेशन लि० में सभी संकटों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : सिकराय	जिला : जयपुर	राज्य : राजस्थान		
ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हैक्टर	ऐयर	वर्गमीटर
सिराय	1536	0	05	06

[सं० 12020/2/78-प्रोड-VIII]

S.O. 3540.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum) S.O. 1443 dated 20-5-1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Setcion 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of the power conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Sikrai	District : Jaipur	State : Rajasthan		
Village	Khasra No.	Area		
		H.	A.	Sq. M.
Sikrai	1536	0	05	06

[No. 12020/2/78-Prod. VIII]

का० आ० 3541.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1444 तारीख 20-5-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इंडियन आयल कारपोरेशन लि० में सभी संकटों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : रायपुर	जिला : पाली	राज्य : राजस्थान		
ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हैक्टर	ऐयर	वर्गमीटर
सराधना	454	0	00	38
	455	0	01	20
	456	0	02	40
	457	0	04	10
	467	0	07	39
	470	0	00	64
	474	0	05	77

[क्रमांक 12020/2/78-प्रौड IX]

S.O. 3541.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum) S.O. 1444 dated 20-5-1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notifiction for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore in exercise of the power conferred by Subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of the power conferred by Subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Raipur	District : Pali	State : Rajasthan		
Village	Khasra No.	Area		
		H.	A.	Sq. M.
Saradhana	454	0	00	38
	455	0	01	20
	456	0	02	40
	457	0	04	10
	467	0	07	39
	470	0	00	64
	474	0	05	77

[No. 12020/2/78-Prod. IX]

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1978

का०आ० 3542.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 898 तारीख 17-3-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संपर्कों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० के० डी० एफ०-4 से कूप नं० के०-7 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात	जिला व तालुका : गांधी नगर			
गांव	सर्वे नं०	हैक्टयर	एआरई	सेन्टीयर
सेरखा	806/1	0	04	95
	806/2	0	10	20
	कार्टट्रैक	0	01	20
	811/5	0	07	15
	839	0	11	95
	840	0	01	50
	838/2/1	0	07	80
	857(2)	0	03	45
	857(1)/2	0	08	40
	857(2)/1	0	11	70
	858/2	0	04	20
	859/3	0	04	95
	859/2	0	03	60
	859/1	0	03	45
	861/2.सी	0	09	60
	861/2.बी	0	04	50
	862/3	0	10	20
	863/1	0	06	00
	914(1)/2	0	06	75
	914(2)/1	0	11	40
	915	0	10	35
	916/2	0	01	00
	911/2	0	14	20
	कार्टट्रैक	0	00	90
	987	0	18	15
	999	0	05	40

[सं० 12016/7/77-प्रौ०]

New Delhi, the 20th November, 1978

S.O. 3542.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 898 dated 17-3-1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Acquisition of R.O.U. in land for laying oil/Gas Pipeline from well No. KEX-4 To well No. K. - 7.

State : Gujarat District & Taluka: Gandhinagar.

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
SERTHA....	806/1	0	04	95
	806/2	0	10	20
	Cart-track	0	10	20
	811/5	0	07	15
	839	0	11	95
	840	0	01	50
	838/2/1	0	07	80
	857(2)	0	03	45
	857(1)/2	0	08	40
	857(2)/1	0	11	70
	858/2	0	04	20
	859/3	0	04	95
	959/2	0	03	60
	859/1	0	03	45
	861/2.C	0	09	60
	861/2.B	0	04	50
	862/3	0	10	20
	863/1	0	06	00
	914(1)/2	0	06	75
	914(2)/1	0	11	40
	915	0	10	35
	916/2	0	01	00
	911/2	0	14	20
	Cart-track	0	00	90
	987	0	18	15
	999	0	05	40

12016/7/77-Prod]

का०आ० 3543.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 3141 तारीख 27-9-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) की सरकार को रिपोर्ट दे दी गई है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस का आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप सं० 212 से कूप सं० 135 तक पाइप लाइन बिछाने के लिये ।

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	सर्वेक्षण सं०	हैक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
भड़ कोदरा	79	0	17	55
ऊमरखाड़ा	410/3/2	0	21	45

[सं० 12016/3/77-प्रोड]

S.O. 3543.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3141 dated 27-9-77 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering that said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Well No. 212 to Well No. 135.

State : Gujarat District : Broach Taluka: Ankleshwar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Bhadkodra	79	0	17	55
Umarwada	410/3/2	0	21	45

[No. 12016|3|77-Prod]

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1978

का०आ० 3544.—भारत सरकार के राजपत्र भाग (ii) खंड 3 उपखंड (ii) दिनांक 20-3-78 की पृष्ठ संख्या 336 पर भारत सरकार के का०आ० 183(ई) के अन्तर्गत प्रकाशित भारत सरकार पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय की, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइनों अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा (i) की अधिसूचना संख्या 12020/7/77 प्रोडक्शन (iii) दिनांक 20-3-78 में प्रविष्टि को मिटा दिया जाये क्योंकि मानचित्र (रेखांकन) में परिवर्तन कर दिया जाने के लिए निम्नलिखित भूमि प्रयोगकर्ता के अधिकार में नहीं आती :—

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टर	ए.आरई०	सैन्टेयर
बोरीपाखड़ी . .	1751/1क	0	02	0

[सं० 12020/7/77–प्रो०]

CORRIGENDUM

New Delhi, 22nd November 1978

S.O. 3544.—In the schedule appended to the notification u/s. 6(1) of the Petroleum & Mineral Pipeline Act 1962 issued by the Government of India, in the Ministry of Petroleum, Chemical & Fertilizer bearing No. 12020/7/77 Prod/III dated 20/3/78, under S. O. 183(E) in the Gazette of India Part I Section 3 Sub-section (ii) dated 20/3/78 Page No. 336, delete the following entry as the land does not fall within the Right of User due to change of alignment.

Village	S. No.	Hectore	Are	Centiare
Boripakhadi	175A/1C	0—	02—	0—

[No. 12020/7/77-Prod.]

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1978

का०आ० 3544.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० धोलका–14 से धोलका–1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतत्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप ल.ईन बिछाने के लिए आक्षेप ,सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड वड़ोदरा–9 की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० धोलका–14 से धोलका–1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात तालुका : मातर जिला : खेड़ा

गांव	सर्वे नं०	हैक्टेयर	ए.आर.ई.	सैन्टीयर
रसिक पुरा .	57/2	0	01	50
	64	0	19	20
		0	01	35

[सं० 12016/12/78–प्रो०]

New Delhi, the 24th November, 1978

S.O. 3545.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Dholka-14 to Dholka-1 in Gujarat State pipelines should laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Well No. Dholka—14 to Dholka—1

State : Gujarat Taluka : Matar District : Kaira

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Rasikpura	57/2	0	01	50
	Cart-track	0	01	35
	64	0	19	20

[No. 12016/12/78-Prod.]

का० आ० 3546.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1134 तारीख 3-4-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) की सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कुआ नं० के-115 से सी० टी० एफ० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : महेसाना		तालुका : कलोल	
गांव	सर्वे नं०	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एआरई	सैण्टीयर
सईज	472/3	0	06	00
	472/2	0	08	85
	472/1	0	01	50
	556/1/3	0	18	30
	556/1/7	0	00	50
	556/1/6	0	05	10
	556/1/4	0	06	30
	556/1/8	0	03	90
	554	0	01	00
	623	0	41	05
	550	0	10	35
	549	0	12	00
	547/3	0	05	10
	547/4	0	04	50

[सं० 12016/4/78—प्रो०-I]

S.O. 3546.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1134, dated 3rd April, 1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And, further, in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. K-115 to CTF

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Saij	472/3	0	06	00
	472/2	0	08	85
	472/1	0	01	50
	556/1/3	0	18	30
	556/1/7	0	00	50
	556/1/6	0	05	10
	556/1/4	0	06	30
	556/1/8	0	03	90
	554	0	01	00
	623	0	41	05
	550	0	10	35
	549	0	12	00
	547/3	0	05	10
	547/4	0	04	50

[No. 12016/4/78-Prod. I]

का०आ० 3547.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 1136 तारीख 3-4-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) की सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० के-22 से जी० जी० एस-7 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : गांधीनगर तालुका : गांधीनगर

गांव	सर्वे नं०	हैक्टेयर	ए.आर.ई	सैण्टीयर
अवारसद	1327/3/1	0	05	52
	1327/3/2	0	01	00
	1327/2	0	10	95
	1344	0	06	45
	1166/4	0	06	60
	1166/5	0	07	05
	1165/2	0	11	25
	893	0	04	50
	1164/1	0	15	65
	1164/2	0	06	00
	894/1	0	09	60
	894/2	0	14	05

[सं० 12016/4/78—प्रो०—II]

S.O. 3547.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1138, dated 3rd April, 1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And, further, in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From D.S. K—22 to GGS 7

State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Uvarsad	1327/3/1	0	05	52
	1327/3/2	0	01	00
	1327/2	0	10	95
	1344	0	06	45
	1166/4	0	06	60
	1166/5	0	07	05
	1165/2	0	11	25
	893	0	04	50
	1164/1	0	15	65
	1164/2	0	06	00
	894/1	0	09	60
	894/2	0	14	05

[No. 12016/4/78-Prod-II]

का० आ० 3548.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 1137 तारीख 3-4-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) की सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

सानन्द-49 से सानन्द-18 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात तालुका : कलोल जिला : मेहसाना

गांव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	एआरई	सेण्टीयर
खाभज	345	0	03	45
	343	0	25	75
	342	0	02	10
	348	0	12	60
	334	0	35	80
	335	0	01	00
	325	0	12	75
	326	0	23	85
	279	0	03	02

[सं० 12016/4/78—प्रो०—III]

S.O. 3548.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1137, dated 3rd April, 1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And, further, in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Sanand—49 to Sanand—18

State : Gujarat Taluka : Kalol District : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Khatraj	345	0	03	45
	343	0	25	75
	342	0	02	10
	348	0	12	60
	334	0	35	80
	335	0	01	00
	325	0	12	75
	326	0	23	85
	279	0	03	02

[No. 12016/4/78-Prod.III]

का० आ० 3549.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1138, तारीख 3-4-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा (1) सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० के—112 (के० आई० पी०) से जी० जी० एस०—6 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : गांधी नगर

गांव	सर्वे नं०	हैक्टेयर	एआरई	सैण्टीयर
1	2	3	4	5
ऊवारसद	1231	0	27	28
	1230/1	0	06	41
	1229	0	17	63
	1157	0	07	10
	1158	0	16	61
	1169/3	0	07	41
	1170/5 व 6	0	12	38
	1170/2/ए	0	05	20
	1170/1	0	04	98
	1171/4	0	02	97
	1171/3	0	02	68
	1152	0	03	90
	1151/6	0	05	62
	1151/5	0	03	46
	1151/4	0	04	99
	1150/6	0	04	99
	कार्ट ट्रैक	0	01	00
	1102/1	0	14	36
	1108	0	06	37
	1107	0	07	80

[सं० 12016/4/78-प्रो०-IV

S. O. 3549.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1138, dated 3rd April, 1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From K—112 to GGS—VII

State : Gujarat District & Taluka : Ganhinagar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Uvarsad	1231	0	27	28
	1230/1	0	06	41
	1229	0	17	63
	1157	0	07	10
	1158	0	16	61
	1169/3	0	07	41
	1170/5 & 6	0	12	38
	1170/2/A	0	05	20
	1170/1	0	04	98
	1171/4	0	02	97
	1171/3	0	02	68
	1152	0	03	90
	1151/6	0	05	62
	1151/5	0	03	46
	115/14	0	04	99
	1150/6	0	04	99
	Cart track	0	01	00
	1102/1	0	14	36
	1108	0	06	37
	1107	0	07	80

[No. 12016/4/78-Prod-IV

का०आ० 3550.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 1139, तारीख 3-4-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार की पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) की सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० जे० एल० एस० से जी० जी० एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं०	हैक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
मेरडा	188/1	0	03	75
	188/2	0	09	00
	185	0	09	65
	191	0	12	90

[सं० 12016/4/78-प्रो० V]

S.O. 3550.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1139, dated 3rd April, 1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. JLL to GGS

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Merda	188/1	0	03	7
	188/2	0	09	00
	185	0	09	65
	191	0	12	90

[No. 12016/4/78-Prod-V

का०आ० 3551.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 1140, तारीख 3-4-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार की पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कुआं नं० एन० के० ए० पी० से जी० जी० एस० कम सी० टी० ओक कड़ी तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात, जिला : मेहसाना, अहमदाबाद तालुका : कड़ी विरमगाम

गांव	सर्वे नं०	हेक्टर	एआरई	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
चालासन	कार्ट ट्रेक	0	03	60
	71	0	15	60
	72	0	14	64
	73	0	03	84
	80/2	0	15	60
	80/5	0	07	56
	76/2	0	13	08
	76/4	0	08	04
	कार्ट ट्रेक	0	00	72

1	2	3	4	5
सूरज	688	0	15	12
	686	0	10	92
बामरोली	59/41	0	05	52
	59/50	0	04	32
	59/49	0	05	04
	59/56	0	06	60
	59/4/4	0	14	52

[सं० 12016/4/78-प्रो० VI]

S. O. 3551.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1140, dated 3rd April, 1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines.

And, further, in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

ROU For Well No. NKAP To GGS-Cuj-CTF Kadi

State : Gujarat Talukas : Kadi & Viramgam Distt. Mehsana & Ahmedaba

Villages	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Chalasan	Cart-track	0	03	60
	71	0	15	60
	72	0	14	64
	73	0	03	84
	80/2	0	15	60
	80/5	0	07	56
	76/2	0	13	08
	76/4	0	08	04
	Cart-track	0	00	72
Suraj	688	0	15	12
	686	0	10	92
Bamroli . . .	59/41	0	05	52
	59/50	0	04	32
	59/49	0	05	04
	59/56	0	06	60
	59/4/4	0	14	52

[No. 12016/4/78-Prod.VI]

का०आ० 3552.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोर्ट से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, बी-18, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर-6 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

तहसील : अजमेर जिला : अजमेर राज्य : राजस्थान

ग्राम	खसरा सं०		क्षेत्रफल		
	पुराना	नया	हैक्टर	ऐआर	वर्गमीटर
अमरगढ़	590	842	0	02	43
मावशिया	198	288	0	04	05
सूरजपुरा	387	459	0	09	71

[सं० 12020/4/78-प्रो०]

एस० एम० वाई० नदीम, अवर सचिव

New Delhi, the 25th November, 1978

S.O. 3552.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited ;

And whereas it appears that for the Purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the Powers conferred by Sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, B-18, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur-6.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to the heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Ajmer District : Ajmer State : Rajasthan

Village	Khasra No.		Area		
	Old	New	H.	A.	Sq.M
Amargarh .	590	842	0	02	43
Mavshya . .	198	288	0	04	05
Surajpura . .	387	459	0	09	71

[No. 12020/4/78-Prod.]

S.M.Y. NADEEM, Under Secy.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1978

का०आ० 3553.—परिसर (अनधिकृत कब्जे की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कानूनी आदेश 1032 दिनांक 2 अप्रैल, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"तालिका

अधिकारी का पद नाम	सार्वजनिक परिसर की श्रेणी और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा
(1)	(2)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०, दुर्गापुर का दुर्गापुर एकक।	दुर्गापुर एकक और उसके टाऊनशिप के लिए हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० अथवा उनकी ओर से उनसे संबंधित अथवा पट्टे पर लिया गया परिसर।"

[फाइल सं० 73(1)/77-एफ-II/एफ.डी.सी]

के० पी० श्रीवास्तव, उप सचिव,

(Department of Chemichal & Fertilizers)

New Delhi, the 18th November, 1978

S.O 3553.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 1032, dated the 2nd April, 1977, Namely:—

For the Table below the said notification, the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE

Designation of the Officer	Categories of the Public Premises and local limits of jurisdiction
1	2
Senior Administrative Officer Durgapur Unit of Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., Durgapur.	Premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the Hindustan Fertilizer Corporation Ltd. for Durgapur Unit and its township."

[F. No. 73(1)/77-F.II/FDC]

K.P. SRIVASTAVA, Dy. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1978

का०आ० 3554.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयला उपलब्ध होने की संभावना है। अतः अब केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) कार्यालय, दरभंगा, हाउस रांची या कलेक्टर सिद्धी (मध्य प्रदेश) के कार्यालय या कोयला नियंत्रक कार्यालय, 1 कौंसिल हाउस, कलकत्ता में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अंतर्गत सम्मिलित भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में वर्णित सभी नक्शे, चार्ट और अन्य दस्तावेजें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी सेन्ट्रल कोलफील्ड, दरभंगा हाउस को भेज देना चाहिए।

अनुसूची

काकरी और मर्रा खण्ड

सिंगरोली कोयला क्षेत्र

जिला मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश

ड्रा० सं० रा०/34/78

तारीख 22-7-78

(पूर्वेक्षण के लिये अधिसूचित भूमि वर्णित करते हुए)

काकरी खण्ड

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	परगना	परगना संख्या	थाना	जिला	क्षेत्र टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	काकरी	दुद्धी	सिंगरोली	77	मिश्र	मिर्जापुर	भाग
2.	परासी	,,	,,	,,	(चैरवा)	,,	,,
3.	रेहरा	,,	,,	,,	,,	,,	,,
4.	बांसी	,,	,,	,,	,,	,,	,,
5.	पन्थ सागर	,,	,,	,,	,,	,,	,,

कुल क्षेत्र 2375.00 एकड़ (लगभग)

या 961.12 हैक्टेयर (लगभग)

सीमा विवरण :

क-ख—रेखा काकरी ग्राम से होकर गुजरती है।

ख-ग—रेखा काकरी ग्राम की पश्चिमी सीमा के एक भाग से (जो उत्तर प्रदेश के काकरी और मध्य प्रदेश के चूड़ीदाह ग्रामों की सम्मिलित सीमा का एक भाग है) होकर गुजरती है।

ग-घ/2/ङ—रेखा काकरी और बांसी ग्रामों से होकर गुजरती है।

घ-घ/2/क—रेखा पंच सागर से होकर गुजरती है।

ङ-च—रेखा रेहटा ग्राम के दक्षिणी और पूर्वी सीमा के साथ-साथ (जो पंच सागर की सम्मिलित सीमा का एक भाग है) गुजरती है।

च-छ—रेखा रेहटा और गरखन्धा ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ गुजरती है।

छ-ज-क—रेखा पकरासी और काकरी ग्रामों से होती हुई आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिल जाती है।

मरीक खण्ड

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	परगना	परगना सं०	थाना	जिला	क्षेत्र टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भैरवा	दुद्धी	सिंगरौली	—	मिश्रा	मिर्जापुर	भाग
2.	मिश्रा	,,	,,	102	(भैरवा)	,,	,,
3.	कोहरोलिया	,,	,,	85	,,	,,	,,
4.	कोहरोल	,,	,,	84	,,	,,	,,
5.	जोगी-चौरा	,,	,,	46	,,	,,	,,
6.	मरीक	,,	,,	91	,,	,,	पूर्ण
7.	परसवार राजा	,,	,,	—	,,	,,	भाग
8.	खैरा	,,	,,	115	,,	,,	,,
9.	चिलकन्दर	,,	,,	49	,,	,,	,,

कुल क्षेत्र : 2560.00 एकड़ (लगभग)
या : 1035.98 हैक्टेयर (लगभग)

सीमा विवरण :

झ-ञ—रेखा भैरवा, जोगी चौरा, परसवार राजा, खैरा और चिलकन्दर ग्रामों से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 4 (1) के अधीन अधिसूचित उत्तर प्रदेश के दुद्धी-चौरा खण्ड – II के क्षेत्र की सम्मिलित सीमा का एक भाग है) गुजरती है।

ट-ठ—रेखा, चिलकन्दर और कोटा ग्रामों की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ-साथ और खारिया तथा कोटा ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ गुजरती है।

ठ-ड—रेखा खारिया तथा परसवार चौबे ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ गुजरती है।

ड-ढ—रेखा परसवार राजा और पारसवार बाबू ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ साथ गुजरती है।

ढ-ण—रेखा परसवार राजा, मरीक, जोगी चौरा, भैरवा, मिश्रा कोहरोल और कोहरोलिया ग्रामों की ग्राम सीमा (जो पंच सागर क्षेत्र की सम्मिलित सीमा है) के साथ साथ गुजरती है।

ण-त-थ-द-ध—रेखा कोहरोलिया और बसारी ग्रामों की सम्मिलित सीमा के एक भाग से होती आगे कोहरोलिया, कोहरोल, मिश्रा और भैरवा ग्रामों से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन बीना खण्ड के लिए अधिगृहीत क्षेत्र की सम्मिलित सीमा है) गुजरती है।

ध-झ—रेखा अयसीला और भैरवा ग्रामों की सम्मिलित सीमा के एक भाग से होकर गुजरती है (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन बीना ब्लाक के लिए अधिगृहीत क्षेत्र की सम्मिलित सीमा है) और आरंभिक बिंदु 'झ' पर मिल जाती है।

[सं० 19(44)/78-सी० एल०-II]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 20th November, 1978

S.O. 3554.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

2. The plan of the area covered by this notification can be inspected at the Office of the Central Coalfields Limited, (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi, or at the Office of the Collector, Mirzapur, (Uttar Pradesh), or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of Section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi, within 90 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Kakari & Marrak Blocks

Singrauli Coalfield

District Mirzapur

Uttar Pradesh

Drg. No. Rev/34/78
Dated 22-7-1978
(showing lands notified for prospecting)

Kakari Block

Serial Number.	Village	Tehsil	Pargana	Pargana Number	Thana	District	Area	Remarks
1.	Kakari . .	Dudhi	Singrauli	77	Misra (Khairwa)	Mirzapur	Part	
2.	Parasi . .	,,	,,	—	,,	,,	,,	
3.	Rehata . .	,,	,,	—	,,	,,	Full	
4.	Banshi . .	,,	,,	8	,,	,,	,,	
5.	Pantha Sagar .	,,	,,	—	,,	,,	,,	

TOTAL AREA : 2375.00 acres (approximately)
or : 961.12 hectares (approximately)

Boundary description :

A–B line passes through village Kakari.

B–C line passes along the part western boundary of village Kakari (which forms part common boundary of village Kakari of Uttar Pradesh and village Churidah of Madhya Pradesh.

C–D line passes through villages Kakari, Banshi.

D–D/1/E lines pass through Panth Sagar.

E–F line passes along the sounthern and eastern boundary of village Rehata (which forms part common boundary of Panth Sagar).

F–G line passes along the common boundary of villages Rehata and Garbandha.

G–H–A lines pass through villages Parasi and Kakari and meets at starting point 'A'.

Marrack Block

Serial Number	Village	Tahsil	Pargana	Pargana Number	Thana	District	Area	Remarks
1.	Bhairwa. .	Dudhi	Singrauli	—	Misra (Khairwa)	Mirzapur	Part	
2.	Mishra . .	,,	,,	101	,,	,,	,,	
3.	Koharoulla .	,,	,,	85	,,	,,	,,	
4.	Koharoul .	,,	,,	84	,,	,,	,,	
5.	Jogichoura .	,,	,,	46	,,	,,	,,	
6.	Marrack .	,,	,,	91	,,	,,	Full	
7.	Paraswar Raja .	,,	,,	—	,,	,,	Part	
8.	Kharia .	,,	,,	115	,,	,,	,,	
9.	Chilkadanr .	,,	,,	49	,,	,,	,,	

TOTAL AREA : 2560.00 acres (approximately)
or : 1035.98 hectares (approximately)

Boundary description :

I–J–K line pass through villages Bhairwa, Jogichoura, Paraswar Raja, Kharia & Chilkadanr (which forms part common boundary of the area notified u/s 4(1) of the Coal Act for Dudhichura Block-II in Uttar Pradesh).

K–L lines passes along the part common boundary of villages Chilkadanr & Kota and along common boundary of villages Kharia & Kota.

L–M line passes along the common boundary of villages Kharia & Parasawar Chaube.

M–N line passes along the common boundary of villages Paraswar Raja & Paraswar Babu.

N–O line passes along the village boundary of villages Paraswar Raja, Marrak, Jogichoura, Bhairwa, Mishra, Koharoul & Koharoulia (which forms common boundary of Panth Sagar area).

O–P–Q–R–S lines pass along the part common boundary of villages Koharoulla and Dhasari, then through villages Koharoulia, Koharoul, Mishra & Bhairwa (which forms common boundary of the area's acquired for Bina Block u/s 9(1) of the Coal Act).

S–I line passes along the part common boundary of villages Jaysila and Bhairwa (which forms part common boundary of the area acquired u/s 9(1) of the Coal Act for Bina Block) and meets at starting point 'I'.

[No. 19(44)/78-CL(ii)]

का०आ० 3555.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयला उपलब्ध होने की संभावना है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची या कलक्टर, सिद्धी (मध्य प्रदेश) के कार्यालय या कोलया नियंत्रक कार्यालय, 1 कौंसिल हाउस, कलकत्ता में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत सम्मिलित भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में वर्णित सभी नक्शे, चार्ट और अन्य दस्तावेजें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी सैन्ट्रल कोलफील्ड, दरभंगा हाउस भेज देना चाहिए।

अनुसूची

मुहेर, अमलोड़ी, निगाही, छिगुंदा विस्तार और काकोरी विस्तार खण्ड, सिंगरौली कोयला क्षेत्र
जिला सिद्धी
मध्य प्रदेश

डा सं० रैक्यू/35/78

तारीख 22-7-78
(पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शित करते हुए)

मुहेर खण्ड :

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	तहसील संख्या	जिला	टिप्पण क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
1.	अमलौड़ी	सिंगरौली	6	सिद्धी	भाग
2.	मुहेर	"	476	"	"
3.	पड़ारी	"	305	"	"
4.	चिनगी टोला	"	173	"	"
5.	पुकरा रामगढ़	"	—	"	"
6.	चोकारा	"	176	"	"

कुल क्षेत्रफल : 5840.00 एकड़ (लगभग)
या 2363.33 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा-वर्णन

क–ख रेखा मुहेर, पड़ारी और चिनगीटोला ग्रामों से होकर गुजरती है।

ख–ग रेखा चिनगीटोला, पुकररामगढ़ ग्रामों से होकर चोकरा ग्राम को भागतः पश्चिमी सीमा के साथ-साथ गुजरती है।

ग–घ रेखा चोकरा ग्राम से होकर भागतः अमलोड़ी ग्राम की सीमा के साथ-साथ गुजरती है।

घ–ङ रेखा अमलोड़ी और मुहेर ग्रामों से होकर गुजरती है।

ङ–च रेखा मुहेर ग्राम से गुजरती है और आरम्भिक बिन्दु क पर मिल जाती है।

अमलोड़ी खण्ड :

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	तहसील संख्या	जिला	टिप्पण क्षेत्रफल
1.	अमलोड़ी	सिंगरौली	6	सिद्धी	भाग
2.	मुहेर	"	476	"	"
3.	नौगढ़	"	—	"	"
4.	कांचनी	"	—	"	"
5.	दसोती	"	—	"	पूर्ण
6.	भरवा	"	181	"	"
7.	कोल भोरवा	"	41	"	"
8.	पुरेवा	"	309	"	भाग
9.	अमझर	"	7	"	"
10.	नवानगर	"	129	"	"
11.	भाजनकला	"	—	"	"

कुल क्षेत्रफल : 5915.00 एकड़ (लगभग)
या 2393.68 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा वर्णन

क–घ रेखा मुहेर और अमलोड़ी ग्रामों से होकर गुजरती है [जो मुहेर खण्ड (ब्लाक) की सामान्य सीमा है]।

घ–ज रेखा अमलोड़ी, नौगढ़ ग्रामों से होकर गुजरती है।

ज–छ रेखा नौगढ़ कांचनी, भाजन कला और नवा नगर ग्रामों से होकर गुजरती है।

छ–च रेखा नवा नगर, अमझर, पुरेवा, और मुहेर ग्रामों से होकर गुजरती है।

च–क रेखा मुहेर ग्राम से होकर गुजरती है और आरम्भिक बिन्दु क पर मिल जाती है।

निगाही खण्ड:

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	तहसील संख्या	जिला	टिप्पण क्षेत्रफल
1.	मधौली	सिंगरौली	446	सिद्धी	भाग
2.	निगाही	"	288	"	"
3.	छान पाथर	"	184	"	पूर्ण
4.	पुरेवा	"	309	"	भाग
5.	मुहेर	"	476	"	"
6.	अमझर	"	7	"	"
7.	नालनगर	"	129	"	"
8.	पुरौली खुर्द	"	117	"	"
9.	घुरौली कला	"	116	"	"
10.	इटवा	"	—	"	"
11.	बिलौली	"	170	"	"
12.	पिपरा लाल टोला	"	—	"	"
13.	जैतपुर	"	—	"	"
14.	सरसाबाह राजाटोला	"	224	"	"
15.	गरवा	"	—	"	"
16.	मुड़बनी	"	205	"	"

कुल क्षेत्रफल 6020.00 एकड़ (लगभग)
या 2436.17 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा विवरण:

च–छ रेखा, मुहेर, पुरेखा, अमझर और नवानगर (जो अमलोड़ी खण्ड की सामान्य सीमा है) से होकर गुजरती है।

छ–फ रेखा नवानगर, धुरौली, खुर्द, धुरौली कला, इटवा, बिनौली, पिपरालाल टोला और जैतपुर ग्रामों से होकर गुजरती है।

झ–ञ रेखा जैतपुर और सरसाबाह लाल टोला ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ-साथ और आगत: सरसाबाह राजा टोला और सरसाबाह लाल टोला ग्रामों की सामान्य सीमा से होकर गुजरती है।

ञ–ठ–ठ-ड–ड रेखाएं सरसोवा राजाटोला, जैतपुर, गरवा ग्रामों से होकर आगत:,गरवा और मुढबनी तथा मुढबनी और बिनौली ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ-साथ मुढबनी, निगाही और मथौली ग्रामों से [जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अधिगृहीत जयन्त ब्लाक की सामान्य सीमा है] होकर गुजरती है ।

ड–ब रेखा मथौली, निगाही और मुहेर ग्रामों से होकर गुजरती है तथा आरम्भिक बिन्दु च पर मिल जाती है।

झिंगुरदा विस्तार खण्ड :

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	तहसील संख्या	जिला	क्षेत्रफल	टिप्पण
1.	चुरकी	देवसर	—	सिद्धी	भाग	
2.	झिंगुरदा	सिंगरौली	206	—	—	

कुल क्षेत्रफल : 1460.00 एकड़ (लगभग)
या 590.83 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा विवरण :

ण–त रेखा देवसर तहसील के चुर्की ग्राम और सिंगरौली तहसील के झिंगुरदा ग्रामों से होकर गुजरती है।

त–द रेखा झिंगुरदा ग्राम [जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन झिंगुरदा ब्लाक में अधिगृहीत क्षेत्र की सामान्य सीमा का एक भाग है] से होकर गुजरती है।

द–ध रेखा देवसर तहसील के चुर्की और सिंगरौली तहसील के झिंगुरदा ग्राम की सामान्य सीमा के साथ साथ [जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अधिगृहीत झिंगुरदा ब्लाक की सामान्य सीमा का एक भाग है] से होकर गुजरती है ।

ध–क रेखा झिंगुरदा ग्राम से [जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अधिगृहीत झिंगुरदा ब्लाक की सामान्य सीमा का एक भाग है] होकर गुजरती है।

क–न रेखा सिंगरौली तहसील के झिंगुरदा और देवसर तहसील के चुर्की ग्रामों से होकर गुजरती है।

न–ण रेखा देवसर तहसील के चुर्की ग्राम से होते हुए गुजरती है और आरम्भिक बिन्दु ण पर मिल जाती है।

कंकरी विस्तार खण्ड :

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	तहसील संख्या	जिला	क्षेत्रफल	टिप्पण
1.	चूड़ीवाह	सिंगरौली	—	सिद्धी	भाग	

कुल क्षेत्रफल : 82.00 एकड़ (लगभग)
या 33.18 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा विवरण :

प–फ–ब रेखा चूड़ीवाह ग्राम से होकर गुजरती है।

ब–प रेखा चूड़ीवाह ग्राम की आगत: पूर्वी सीमा से होकर गुजरती है (जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सामान्य सीमा का एक भाग है और जो उत्तर प्रदेश के काकोरी ब्लाक के एक भाग की भी सीमा रेखा है)

[सं० 19(44)/78 सी एम (i)]
एस० आर० ए० रिजवी, निदेशक

S.O 3555.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the schedule hereto annexed ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

2. The plan of the area covered by this notification can be inspected at the Office of the Central Coalfields Limited, (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi, or at the Office of the Collector, Sidhi (Madhya Pradesh), or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of Section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi, within 90 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Muher, Amlori, Nigahi, Jhingurda Extn. & Kakri Extn. Blocks

Singrauli Coalfields

District Sidhi

Madhya Pradesh

Drg. No. Rev/35/78
Dated 22-7-78

(showing lands notified for prospecting)

Muher Block

Serial Number	Village	Tahsil	Tahsil Number	District	Area	Remarks
1.	Amlori	Singrauli	6	Sidhi		Part
2.	Muher	,,	476	,,		,,
3.	Padari	,,	305	,,		,,
4.	Chinagi tola	,,	173	,,		,,
5.	Pukra ramgarh	,,	..	,,		,,
6.	Chokara	,,	178	,,		,,

TOTAL AREA : 5840.00 acres (approximately)
or 2363.33 hectares (approximately)

Boundary description :

A–B line passes through villages Muher, Padari and Chinagitola.

B–C line passes through villages Chinagitola, Pukra Ramgarh, along the part western boundary of village Chokara.

C–D line passes through village Chokara and along the village boundary of part southern boundary of Amlori village.

D–E line passes through villages Amlori and Muher.

E–A line passes through village Muher and meets at starting point 'A'.

Amlori Block

Serial No.	Village	Tehsil	Tehsil Number	District	Area	Remarks
1.	Amlori	Singrauli	6	Sidhi		Part
2.	Muher	,,	476	,,		,,
3.	Naugarh	,,	..	,,		,,
4.	Kachani	,,	..	,,		,,
5.	Dasauti	,,	..	,,		Full
6.	Bharwa	,,	181	,,		,,
7.	Kol Bhorwa	,,	41	,,		,,
8.	Purewa	,,	309	,,		Part
9.	Amjhar	,,	7	,,		,,
10.	Nawa Nagar	,,	129	,,		,,
11.	Majan Kala	,,	..	,,		,,

TOTAL AREA : 5915.00 acres (approximately)
or 2393.68 hectares (approximately)

Boundary description :

E–D line passes through villages Muher and Amlori (which forms common boundary with Muher Block).

D–H line passes through villages Amlori, Naugarh.

H–G line passes through villages Naugarh, Kachani, Majan Kala and Nawa Nagar.

G–F line passes through villages Nawa Nagar, Amjhar, Purewa and Muher.

F–E line passes through village Muher and meets at starting point 'E'.

Nigahi Block

Serial Number	Village	Tehsil	Tehsil Number	District	Area	Remarks
1.	Madhauli	Singrauli	446	Sidhi	Part	
2.	Nigahi	,,	288	,,	,,	
3.	Chhan Pathar	,,	184	,,	Full	
4.	Purewa	,,	309	,,	Part	
5.	Muher	,,	476	,,	,,	
6.	Amjhar	,,	7	,,	,,	
7.	Nawa Nagar	,,	129	,,	,,	
8.	Ghorauli Khurd	,,	117	,,	,,	
9.	Ghorauli Kala	,,	116	,,	,,	
10.	Itwa	,,	..	,,	,,	
11.	Binauli	,,	170	,,	,,	
12.	Pipra Lal tola	,,	..	,,	,,	
13.	Jaitpur	,,	..	,,	,,	
14.	Sarsobah Raja Tola	,,	224	,,	,,	
15.	Garda	,,	,,	,,	,,	
16.	Murhbani	,,	205	,,	,,	

TOTAL AREA : 6020.00 acres (approximately)
or 2436.17 hectares (approximately)

Boundary description :

F–G line passes through villages Muher, Purewa, Amjhar and Nawa Nagar (which forms common boundary with Amlori Block).

G–I line passes through villages Nawa Nagar, Ghorauli Khurd, Ghorauli Kala, Itwa, Binauli, Pipra Lal Tola and Jaitpur.

I–J line passes along the common boundary of villages Jaitpur and Sarsobah Lal Tola and part common boundary of villages Sarsobah Raja Tola and Sarsobah Lal tola.

J–K–L–M–N–lines pass through villages Sarsobah Raja tola, Jaitpur, Garda, along part common boundary of villages Garda & Murhbani and Murhbani & Binauli, through villages Murhbani, Nigahi & Madhouli (which forms common boundary of Jayant Block acquired under section 9(1) of the Coal Act.)

N–F line passes through villages Madhauli, Nigahi and Muher and meets at starting point 'F'.

Jhingurda Extension Block

Serial Number	Village	Tahsil	Tahsil Number	District	Area	Remarks
1.	Churki	Deosar	..	Sidhi	Part	
2.	Jhingurda	Singrauli	206	,,	,,	

TOTAL AREA : 1460.00 acres (approximately)
or 590.83 hectares (approximately).

Boundary description :

O–P line passes through village Churki of Deosar Tahsil and Jhingurda of Singrauli Tahsil.

P–Q line passes through village Jhingurda (which forms part common boundary of the area acquired under section 9(1) of the Coal Act for Jhingurda Block).

Q–R line passes along the part common boundary of villages Churki of Deosar Tahsil and village Jhingurda of Singrauli Tahsil [which forms part common boundary of Jhingurda Block acquired under section 9(1) of the Coal Act].

R–S line passes through village Jhingurd (which forms part common boundary of Jhingurda Block acquired u/s 9(1) of the Coal Act).

S–T line passes through village Jhingurda of Singrauli Tahsil and Churki of Deosar Tahsil.

T–O line passes through village Churki of Deosar Tahsil and meets at starting point 'O'.

Kakari Extension Block

Serial Number	Village	Tansil	Tahsil Number	Distriot	Area	Remarks
1.	Churidah	Singrauli	..	Sidhi	Part	

TOTAL AREA : 82.00 acres (approximately)
or 33.18 hectares (approximately)

Boundary description :

U–V–W lines pass through village Churidah.

W–U line passes along the part eastern boundary of village Churidah (which forms part common boundary of Madhya Pradesh and Uttar Padesh and also forms with part of Kakari Block of Uttar Pradesh area).

[No. 19(44)/78-CL(I)]
S.R.A. RIZVI, Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1978

का०आ० 3556:—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102 वां) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के साथ परामर्श करने के उपरान्त एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः

उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में मिथिला विश्व-विद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों के अन्तर्गत निम्नलिखित वाक्यांश को हटा दिया जायेगा, नामतः

" इस अर्हता को केवल तभी चिकित्सीय अर्हता माना जाएगा जब वह 5 फरवरी, 1975 को अथवा उससे पहले प्रदान की गई हो।

[सं० वी० 11015/13/78- एम० ई० (पी)]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 22nd November, 1978

S.O. 3556.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government after consulting Medical Council of India hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely :—

In the First Schedule to the said Act, the following clause appearing under the entries relating to Mithila University shall be omitted, namely :—

"This qualification shall be recognised medical qualification only when granted on or before the 5th February, 1975."

[No. V. 11015|13|78-M.E.(P)]

का०आ० 3557:—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप धारा (i) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसरण में कानपुर विश्वविद्यालय ने चिकित्सा संकाय में डीन एवं जी० एस० एम० मेडिकल कालेज में प्रधानाचार्य डा० हरिशचन्द्र वर्मा को 23 जुलाई, 1978 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना सं० एस० ओ० 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (i) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 49 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"49 डा० हरिशचन्द्र वर्मा,
डीन, चिकित्सा संकाय एवं प्रधानाचार्य,
जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर"।

[सं० वी० 11013/1/78- एम० ई० (पी)]

आर० वी० श्रीनिवासन्, उप सचिव

S.O. 3557.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (i) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Dr. Harish Chandra Verma, Dean Faculty of Medicine and Principal G.S.V.M. Medical College, Kanpur, has been elected by the Kanpur University to be a member of the Medical Council of India with effect from the 23rd July, 1978 ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the late Ministry of Health No. S.O. 138 dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification under the heading "Elected under clause (b) of Sub-section (1) of section 3", for Serial No. 49 and the entry relating thereto, the following serial No. and entry shall be substituted, namely :—

"49. Dr. Harish Chandra Verma,
Dean, Feculty of Medicine and
Principal, G. S. V. M. Medical College,
KANPUR."

[No. V. 11013|1|78-M.E. (Policy)]

R. V. SRINIVASAN, Secy.

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1978

का० आ० 3558:—लोक परिसर (अधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा डा० सी० के० राव, उप निदेशक को सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी होने के नाते डा० बी.एल. वट्टल, उप निदेशक के स्थान पर राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान 22 शामनाथ मार्ग, दिल्ली में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है और निदेश देती है कि उक्त अधिकारी राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान-22 शामनाथ मार्ग, दिल्ली से और उसके प्रशासकीय नियंत्रण से संबंधित पट्टे पर लिए गये या उक्त संस्था की ओर से लिये गये परिसरों के बारे में उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अंतर्गत सम्पदा अधिकारियों को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गये कर्तव्यों को करेगा।

[संख्या टी० 17020/12/77-सी० सी०डी०]

आनन्द प्रकाश अत्री, उपसचिव,

(Department of Health)

New Delhi, the 23rd November, 1978

S.O. 3558.—In exercise of the powers, conferred by Setcion 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints Dr. C. K. Rao, Deputy Director in place of Dr. B.L. Wattal, Deputy Director, at the National Institute of Communicable Diseases, 22-Shamnath Marg, Delhi, being a Gazetted Officer of the Government, as Estate Officer for the purposes of the act, and directs that the said Officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act, in respect of the premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the National Institute of Communicable Diseases, 22-Shamnath Marg, Delhi, and under the Administrative control of the said Institute.

[No. T. 17020|12|77-CCD]

ANAND PRAKASH ATRI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1978

का०आ० 3559.—यतः केन्द्रीय सरकार ने दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16वां) की धारा 3 की खण्ड (घ) के अनुसरण में डा० सत्य पाल सचदेव को 28 सितम्बर, 1978 से भारतीय दन्त-चिकित्सा परिषद् का सदस्य मनोनीत किया है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 25 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में पृष्ठ 579 पर एस०ओ० 533 दिनांक 9 फरवरी, 1978 के रूप में पुनः प्रकाशित अद्यतन तथा संशोधित भारत सरकार

के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 12 अप्रैल, 1948 की अधिसूचना संख्या 10-10/48—एम० .1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना में शीर्षक "धारा 3 के खण्ड (च) के अन्तर्गत मनोनीत" के अन्तर्गत क्रम संख्या 6 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"6. डा० सत्यपाल सचदेव डा० सचदेव लेन, 7, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002.	केन्द्रीय सरकार	28-9-1978"

[संख्या वी० 12013/2/78—पी० एम० एस०]
एन० ए० सुब्रामनी, अवर सचिव

New Delhi, the 25th November, 1978

S.O. 3559.—Whereas the Central Government have in pursuance of clause (f) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), nominated Dr. Satya Pal Sachdev, to be a member of the Dental Council of India, with effect from the 28th September, 1978;

Now, Therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. F.10-10/48-MI, dated the 12th April, 1948 as republished as amended up-to-date in the Gazette of India Part II-Section 3-Sub-section (ii), dated the 25th February, 1978 as S.O. 533, dated 9th February, 1978 on page 579, namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (f) of section 3", for serial No. 6 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"6. Dr. Satya Pal Sachdev, Dr. Sachdev Lane, 7, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002.	Central Government	28-9-1978"

[No. V. 12013/2/78-PMS]
N.A. SUBRAMONEY, Under Sec.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(Department of Food)

New Delhi, the 4th December, 1978

CORRIGENDA

S.O. 3560.—In the order of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. SO 695(E) dated 1-12-1978 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3—Sub-section (ii) dated 1-12-1978 :—

at page 1496—
in the penultimate line of the penultimate para,
for the word "liability"
read "inability"

[No. SUG/112/78-79]

S.O. 3561.—In the order of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. SO 696(E) dated 1-12-1978 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3—Sub-section (ii) dated 1-12-1978 :—

at page 1496—
in the penultimate line of the penultimate para,
for the word "liability"
read "inability"

[No. SUG/104/78-79]
C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1978

का०आ० 3562.—मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 में और संशोधन करने के लिए एक स्कीम का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है; और यह सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दो मास बीतने पर या उसके पश्चात उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप के बारे में जो भी आक्षेप या सुझाव इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का नाम मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1978 है ।

2. मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 में,—

(i) खण्ड 16 के उपखण्ड (2) की मद (ग) में "विचमैन" शब्द के स्थान पर "विच ड्राइवर" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खण्ड 42 में पार्श्व शीर्ष सहित जहां कहीं भी "विच मैन" शब्द आया है उसके स्थान पर "विच ड्राइवर" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) अनुसूची-1 की मद (2) की उप मद (ग) में "विच मैन" शब्द के स्थान पर "विच ड्राइवर" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) अनुसूची 2 में "विच मैन" शब्द के स्थान पर "विच ड्राइवर" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० एल०डी०एम०/17/78]

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT
(Transport Wing)

New Delhi, the 23rd November, 1978

S.O. 3562.—The following draft of a Scheme further to amend the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1978.

2. In the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956,—

(i) in item (c) of sub-clause (2) of clause 16; for the word 'Winchman', the word 'Winch Driver' shall be substituted;

(ii) in clause 42 including the marginal heading, for the word 'Winchman', wherever it occurs, the word 'Winch Driver' shall be substituted;

(iii) in sub-item (c) of item (2) in Schedule I, for the word 'Winchman', the word 'Winch Driver' shall be substituted;

(iv) in Schedule II for the word 'Winchman', the word 'Winch Driver' shall be substituted.

[No. LDM/17/78]

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1978

का०आ० 3563.—केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियम) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 8 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन नियम 1978, है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन, नियम, 1962 में, नियम 4 में, अन्तिम वाक्य में, "इस नियम के अधीन प्रत्येक रिक्ति" शब्दों के पश्चात्, "जिसमें किसी सदस्य की मृत्यु से हुई रिक्ति भी सम्मिलित है" शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

[एल०बी०-6/174/78-एल०-III]
वी० शंकरलिंगम, अवर सचिव

New Delhi, the 24th November, 1978

S.O. 3563.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) and (2) of section 8 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, in rule 4, in the last sentence, after the words "Every vacancy under this rule" the words "including a vacancy occurring by reason of the death of a member," shall be inserted.

[LDO/174/78-L. III]
V. SANKARALINGAM, Under Secy.

परमाणु ऊर्जा विभाग

बम्बई, 20 अक्तूबर, 1978

का०आ० 3564.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 12 के उप नियम (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त, तथा इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए अधिकार देने वाली अन्य सभी, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देते हैं कि परमाणु ऊर्जा विभाग अथवा उसके किसी भी यूनिट में सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ख' में शामिल केन्द्रीय सिविल पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त नियम के नियम 11 में विनिर्दिष्ट दण्डों में से कोई भी दंड परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव दे सकेंगे। उनका यह अधिकार केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1965 के अन्तर्गत उपर्युक्त वर्ग के अधिकारियों को उक्त दण्डों में से कोई भी दण्ड देने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की शक्ति को प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं करेगा।"

राष्ट्रपति के आदेश से एवं उनके नाम में

[संख्या सी-14011(1)/78-बी०ए०आर०सी०]

पी० बी० देसाई, निदेशक

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay, the 20th October, 1978

S.O. 3564.—In exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-rule (2) of Rule 12 of Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, and all other enabling powers in this behalf, the President hereby directs that in respect of person appointed to Central Civil posts included in the General Central Service, Group B in the Department of Atomic Energy or in any of its constituent units, any of the penalties specified in Rule 11 of the said Rules may be imposed by the Secretary, Department of Atomic Energy. This is without prejudice to the powers of any other authority to impose any of the said penalties on the said class of officers under the Central Civil Services (Classification, Contol and Appeal) Rules, 1965.

By order and in the name of the President

[No. C-14011(1)/78-BARC]

P.B. DESAI, Director

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1978

का०आ० 3565.—यतः, केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच शर्तों पर सहमति हो गई है कि जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट नजूल भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपने कब्जे में ले लिया जायेगा।

अतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 22 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित नजूल भूमि को हरित भूमि के रूप में विकास करने और अनुरक्षण के प्रयोजन तथा उक्त प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के सुपुर्द इस शर्त पर करती है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण उक्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य न करे या न करने दे या निर्माण करने की अनुमति न दे तथा केन्द्रीय सरकार को जब भी इसकी आवश्यकता होगी, उस भूमि को या उसके किसी भाग को जैसी भी आवश्यकता हो केन्द्रीय सरकार को लौटा देगा।

सारणी

क्रम संख्या	स्थान के ब्यौरे	फुल क्षेत्र	अनुसूची
1	2	3	4
1.	वाटर वर्क्स मेगजिन रोड	22.91 एकड़	उत्तर में वाटर वर्क्स दक्षिण में वाटर वर्क्स पूर्व में राष्ट्रीय वाहन मार्ग पश्चिम में वाटर वर्क्स मैगजीन रोड ।
2.	मिन्टो रोड क्षेत्र में प्रसूति अस्पताल के समीप बैरन रोड पर स्थल ।	0.047 एकड़	मिन्टो रोग क्षेत्र
3.	1 से 21 टैगोर लेन 2 से 6 टैगोर रोड़	0.758 एकड़	,,
4.	1 से 7 बैरन रोड	0.344 एकड़	,,
5.	10 टैगोर लेन तथा 8 से 66 टैगोर रोड	0.516 एकड़	,,
6.	44 तथा 46 थाम्पसन वार्ड	0.147 एकड़	,,
7.	1 से 5 टैगोर रोड	0.382 एकड़	,,
8.	40 बैरन रोड	0.170 एकड़	,,
9.	42 से 72 बैरन रोड	0.764 एकड़	,,
10.	2 से 8 मिन्टो रोड तथा 46 से 56 टैगोर रोड	0.610 एकड़	,,
11.	5 और 7 आहिल्या रोड	0.118 एकड़	,,
12.	13 मिन्टो रोड	0.118 एकड़	,,
13.	2 से 40 रणजीत रोड	4.129 एकड़	,,
14.	21 से 23 मीरवर्द रोड	0.278 एकड़	,,
15.	53 से 63 मीरवर्द रोड	1.250 एकड़	,,
16.	10, माता सुन्दरी लेन	0.133 एकड़	,,
17.	14 से 16 माता सुन्दरी लेन	0.367 एकड़	,,
18.	20, कोटला रोड	0.165 एकड़	,,
19.	4, कोटला रोड	0.165 एकड़	,,
20.	154, राऊस ऐवेन्यू	0.165 एकड़	,,
21.	183, 185 राऊस ऐवेन्यू	0.429 एकड़	,,
22.	191 राऊस ऐवेन्यू	0.195 एकड़	,,
23.	153 राऊस ऐवेन्यू	0.022 एकड़	,,
24.	131, 129 राऊस ऐवेन्यू	0.041 एकड़	,,
25.	127 राऊस ऐवेन्यू	0.041 एकड़	,,
26.	103 राऊस ऐवेन्यू	0.041 एकड़	,,
27.	81 राऊस ऐवेन्यू	0.022 एकड़	,,
28.	2 से 6 राऊस ऐवेन्यू	0.053 एकड़	,,
29.	28 से 74 राऊस ऐवेन्यू	0.193 एकड़	,,
30.	55 से 79 राऊस ऐवेन्यू	0.482 एकड़	,,
31.	46 से 70 राऊस ऐवेन्यू	0.610 एकड़	,,
32.	22/20 टैगोर रोड के कोने पर	0.082 एकड़	,,
33.	30/32 टैगोर रोड के कोने पर	0.069 एकड़	,,
34.	64 से 72 थाम्पसन रोड के पीछे	0.115 एकड़	,,
35.	69 टैगोर रोड के पीछे	0.112 एकड़	,,
36.	66-68 टैगोर रोड के कोने पर	0.112 एकड़	मिन्टो रोड क्षेत्र
37.	71-73 बैरन रोड के कोने पर	0.082 एकड़	,,
38.	89-87 बैरन रोड के कोने पर	0.082 एकड़	,,
39.	122 बैरन रोड के साथ	0.185 एकड़	,,
40.	27 से 29 मिन्टो रोड के साथ	0.243 एकड़	,,
41.	35 से 37 मिन्टो रोड के बीच की भूमि	0.109 एकड़	,,
42.	15-17 जहांगीर रोड के पीछे 16-18 प्रेस रोड 40-29 आहिल्या रोड	0.278 एकड़	,, ,,
43.	15-27 प्रेस रोड के पीछे 51-43 आहिल्या रोड 12-20 राऊस ऐवेन्यू	0.253 एकड़	,,
44.	60 मिन्टो रोड के साथ	0.069 एकड़	,,
45.	वाटरटैंक मिन्टो रोड	0.184 एकड़	,,
46.	29-53 जहांगीर रोड के पीछे 22-44 प्रेस रोड, 30-48 प्रेस रोड	0.288 एकड़	,,
47.	55-79 जहांगीर रोड 59-81 तुर्कमान रोड 56-80 प्रेस रोड	0.303 एकड़	,,
48.	29 से 53 प्रेस रोड के पीछे 46 से 54 प्रेस लेन 22 से 30 राऊस ऐवेन्यू	0.303 एकड़	,,
49.	55-79 प्रेस रोड के पीछे 53 से 65 तुर्कमान रोड 32 से 36 राऊस ऐवेन्यू	0.303 एकड़	,,
50.	33-35 राऊस ऐवेन्यू के पीछे 56-62 प्रेस लेन	0.082 एकड़	,,
51.	37-45 राऊस ऐवेन्यू 1-5 तुर्कमान रोड	0.082 एकड़	,,
52	93 प्रेस रोड	0.037 एकड़	,,
53.	तुर्कमान रोड के साथ	0.030 एकड़	,,
54.	3 राऊस ऐवेन्यू के पीछे क्वार्टर नं० 1-13 तथा 30-42	0.137 एकड़	,,
55.	ब्लाक नं० 3, राऊस ऐवेन्यू के पीछे 15-27 तथा 44-52	0.137 एकड़	,,
56.	10-11 तुर्कमान स्क्वेयर के पीछे कोने पर	0.062 एकड़	,,
57.	14-15 तुर्कमान स्क्वेयर के पीछे कोने पर	0.062 एकड़	,,
58.	2/6 राऊस ऐवेन्यू के साथ	0.052 एकड़	,,
59.	मीरवर्द रोड तथा तुर्कमान रोड के मध्य नं० 1	0.329 एकड़	,,
60.	तुर्कमान रोड तथा मीरवर्द रोड के चौराहे पर	0.403 एकड़	,,

1	2	3	4
61.	15-16 प्रेस प्लेस के बीच	0.060 एकड़	मिन्टो रोड क्षेत्र"
62.	18 प्रेस रोड स्थल	0.037 एकड़	,,
63.	112 प्रेस रोड के कोने का स्थल	0.211 एकड़	,,
64.	28 प्रेस लेन के कोने का स्थल	0.037 एकड़	,,
65.	113 प्रेस रोड के पीछे	0.088 एकड़	,,
66.	रेलवे लाइन चहार दीवारी का स्थल	1.322 एकड़	,,

[सं० जे० 13011/6/75-एल० /I/III]

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 17th November, 1978

S.O. 3565.—Whereas the terms and conditions upon which nazul lands specified in the Table below will be taken over by the Delhi Development Authority have been agreed upon between the Central Government and that Authority.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby places, with immediate effect, the nazul lands specified in the table below at the disposal of the Delhi Development Authority for the purpose of Development and maintenance of the said lands as green and for taking such steps as may be required to serve the said purpose, subject to the condition that the Delhi Development Authority should not make, or cause or permit to be made, any construction of the said lands and shall, when required by the Central Government so to do, replace the said lands or any portion thereof as may be so required at the disposal of the Central Government.

TABLE

S. No.	Details of place	Total Area	Schedule
1	2	3	4
1.	Water works Magazine Road	22.91 acres	North by W. Works South by W. Works East by National by pass West by W.W, towards Magazine Road.
2.	Site on Barron Road near Maternity Hospital Minto Road Area	0.047 ,,	Minto Road Area
3.	1 to 21 Tagore Lane 2 to 6 Tagore Road	0.758 ,,	,,
4.	1 to 7 Barron Road	0.344 ,,	,,
5.	10 Tagore Lane and 8 to 66 Tagore Road	0.516 ,,	,,
6.	44 and 46 Thompson Ward	0.147 ,,	,,
7.	1 to 5 Tagore Road	0.382 ,,	,,
8.	40 Barron Road	0.170 ,,	,,
9.	42 to 72 Barron Road	0.764 ,,	,,
10.	2 to 8 Minto Road and 46 to 56 Tagore Road	0.610 acres	Minto
11.	5 and 7 Ahilya Road	0.118 ,,	Road area
12.	13 Minto Road	0.118 ,,	,,
13.	2 to 40 Ranjit Road	4.129 ,,	,,
14.	21 to 23 Mirdard Road	0.278 ,,	,,
15.	53 to 63 Mirdard Road	1.250 ,,	,,
16.	10 Mata Sundry Lnea	0.133 ,,	,,
17.	14 to 16 Mata Sundry Lane	0.367 ,,	,,
18.	20 Kotla Road	0.165 ,,	,,
19.	4 Kotla Road	0.165 ,,	,,
20.	184 Rouse Avenue	0.165 ,,	,,
21.	183, 185 Rouse Avenue	0.429 ,,	,,
22.	191 Rouse Avenue	0.195 ,,	,,
23.	153 Rouse Avenue	0.022 ,,	,,
24.	131, 129 Rouse Avenue	0.041 ,,	,,
25.	127 Rouse Avenue	0.041 ,,	,,
26.	103 Rouse Avenue	0.041 ,,	,,
27.	81 Rouse Avenue	0.022 ,,	,,
28.	2 to 6 Rouse Avenue	0.053 ,,	,,
29.	28 to 74 Rouse Avenue	0.193 ,,	,,
30.	56 to 79 Rouse Avenue	0.482 ,,	,,
31.	46 to 70 Rouse Avenue	0.610 ,,	,,
32.	At corner of 22/20 Tagore Road	0.082 ,,	,,
33.	At corner of 30/32 Tagore Road	0.069 ,,	,,
34.	At back of 64 to 72	0.115 ,,	,,
35.	At the back of 69 Tagore Road	0.112 ,,	,,
36.	At the corner of 66-68 Tagore Road	0.112 ,,	,,
37.	At the corner of 71-73 Barron Road	0.082 ,,	,,
38.	At the corner of 89-87 Barron Road	0.082 ,,	,,
39.	Side of 122 Barron Road	0.185 ,,	,,
40.	Side of 27 to 29 Minto Road	0.243 ,,	,,
41.	Land between 35 to 37 Minto Road	0.109 ,,	,,
42.	Back side of 15-17 Jahangir Road 16-18 Press Road 40-29 Ahilya Road	0.278 ,,	,,
43.	Back side of 15-27 Press Rd. 51-43 Ahilya Road 12-20 Rouse Avenue	0.253 ,,	,,
44.	Side of 60 E Minto Road	0.069 ,,	,,
45.	Water Tank Minto Road	0.184 ,,	,,
46.	Back side 29-53 Jahagir Road 22-44 Press Road, 30-48 Press Road	0.288 ,,	,,
47.	55-79 Jahangir Road, 59-81 Turkman Road, 56-80 Press Road	0.303 ,,	,,
48.	Back side of 29 to 53 Press Road 46 to 54 Press Lane 22 to 30 Rouse Avenue	0.303 ,,	,,

1	2	3	4
49.	At the back of 55-79 Press Road 53 to 65 Turkman Road, 32 to 36 Rouse Avenue .	0.303 acres	Minto Road Area
50.	Back side of 33-35 Rouse Avenue, 50-62 Press Lane. . .	0.082 ,,	,,
51.	37-45 Rouse Avenue, 1-5 Turkman Rd .	0.082 ,,	,,
52.	93 Press Road . .	0.037 ,,	,,
53.	Side of 6 Turkman Road . . .	0.030 ,,	,,
54.	Back of block No. 3, Rouse Avenue, 15-27 and 44-52 . .	0.137 ,,	,,
55.	Back of block 3 Rouse Avenue Qrs. No. 1-13 and 30-42 . . .	0.137 ,,	,,
56.	Corner at the back of 10-11 Turkman Square	0.062 ,,	,,
57.	Corner at the back of 14-15 Turkman Square	0.062 ,,	,,
58.	Side of 2/6 Rouse Avenue . . .	0.052 ,,	,,
59.	Between No. 1, Mirdard Road and Turkman Road . .	0.329 ,,	,,
60.	At the crossing of Turkman Road* .	0.403 ,,	,, *and Mirdard Road.
61.	Between 15-16 Press Place . . .	0.060 ,,	,,
62.	180 Press Road Site .	0.037 ,,	,,
63.	Site corner of 112 press Road . . .	0.211 ,,	,,
64.	Site corner of 28 Press Lane . . .	0.037 ,,	,,
65.	Back of 113 Press Road . . .	0.088 ,,	,,
66.	Site of Railway Line Boundary Wall . .	1.322 ,,	,,

[No. J-13011/6/75-L. I/III]

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1978

का०आ० 3566.—यतः, केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच शर्तों पर सहमति हो गई है जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट नजूल भूमि का दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपने दखल में ले लिया जायेगा ।

अतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 22 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित नजूल भूमि को हरित भूमि के रूप में विकास करने और अनुरक्षण के प्रयोजन तथा उक्त प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के सुपुर्द इस शर्त पर करती है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण उक्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य न करें या न करने दें या निर्माण करने की अनुमति न दे तथा केन्द्रीय सरकार को जब भी इसकी आवश्यकता होगी, उस भूमि को या उसके किसी भाग, जैसी भी आवश्यकता हो, केन्द्रीय सरकार को लौटा देगा ।

क्रम संख्या	स्थान के ब्यौरे	कुल क्षेत्र	अनुसूची
1.	मीरदर्द रोड के उत्तर में जहां यह रोड माता सुन्दरी रोड के साथ मिलता है, उसके समीपस्थ ।	6 एकड़	उत्तर में—इर्विन अस्पताल दक्षिण में—मीरदद रोड तथा सरकारी क्वार्टर पूर्व में—इर्विन अस्पताल तथा 64 खम्बा रोड मस्जिद पश्चिम में—माता सुन्दरी रोड तथा सरकारी क्वार्टर

[सं० जे० 13011/6/75-एल० I/III]
वी० एस० कटारा, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 22nd November 1978

S.O. 3566.—Whereas the terms and conditions upon which nazul lands specified in the Table below will be taken over by the Delhi Development Authority have been agreed upon between the Central Government and that Authority.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby places, with immediate effect, the nazul lands specified in the Table below at the disposal of the Delhi Development Authority for the purpose of development and maintenance of the said lands as green and for taking such steps as may be required to serve the said purpose, subject to the condition that the DelhiDevelopment Authority shall not make, or cause or permit to be made, any construction on the said lands and shall, when required by the Central Government so to do, replace the said lands or any portion thereof as may be so required at the disposal of the Central Government.

TABLE

Location	Area	Schedule of boundary
North of Mirdard Road near its junction with Mata Sundari Road	6 acres	North—Irwin Hospital South—Mirdard Road and Govt. quarters East—Irwin Hospital and 64-Khamba Road Mosque. West—Mata Sundari Road and Govt. quarters

[No. J-13011/6/75-LI/III]
V.S. KATARA, Jt. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1978

का० आ० 3567.—चलचित्र अधिनियम, 1962 की धारा 5(1) और चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 8 के उपनियम (3) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से परामर्श

करने के बाद, एतद्द्वारा निम्नलिखित और व्यक्तियों को तत्काल से अगले आदेश तक, उक्त बोर्ड के मद्रास सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है:—

मलयालम

1. श्री एम० सदानन्द मेनन,
2. श्रीमती आशा जॉर्ज
3. श्रीमती निर्मला मेनन

[फाइल संख्या 11/9/77-एफ०सी०]

सुरेन्द्र कुमार शर्मा, उप-सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 16th November, 1978

S.O. 3567.—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952 and Sub-rule (3) of Rule 8 read with Sub-rule (1) of Rule 9 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby appoints the following more persons, after consultation with the Central Board of Film Censors, as Members of the Advisory Panel of the said Board at Madras with immediate effect until further orders :

MALAYALAM

1. Shri M. Sadanand Menon.
2. Smt. Asha George.
3. Smt. Nirmala Menon.

[F. No. 11/9/77-FC]

S. K. SHARMA, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1978

का०आ० 3568.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने तुरकायामजल व हैयाथनगर टेलीफोन केन्द्रों में दिनांक 16-12-78 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-8/78-पी०एच०बी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 24th November, 1978

S.O. 3568.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-12-78 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Turkayamjal and Hyathnagar Telephone Exchange, Andhra Circle.

[No. 5-8/78-PHB]

का०आ० 3569.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक तार महानिदेशक ने कासगंज टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-1-79 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-3/78पी०एच०बी]

S.O. 3569.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-1-79 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kasganj Telephone Exchange, U.P. Circle.

[No. 5-3/78-PHB]

का०आ० 3570.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने मालाप्पुरम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-12-78 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-10/78 पी०एच०बी]

S.O. 3570.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-12-78 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Malappuram Telephone Exchange, Kerala Circle.

[No. 5-10/78-PHB]

का०आ० 3571.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने वृद्धाचलम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-1-1979 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-25/78-पी०एच०बी०]

S.O. 3571.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-1-1979 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Vridhachalam Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-25/78-PHB]

का०आ० 3572.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने देहगाम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-1-79 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-27/78-पी०एच०बी०]

S.O. 3572.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-1-79 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Dehgam Telephone Exchange, Gujarat Circle.

[No. 5-27/78-PHB]

का०आ० 3573.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने नेटयाटिंकारा टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-1-79 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-10/78-पी०एच०बी०]

ह० अपठनीय

सहायक महानिदेशक (पी०एच०बी०)

S.O. 3573.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-1-79 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Neyyattinkara Telephone Exchange, Kerala Circle.

[No. 5-10/78-PHB]

Sd/- Illegible

Assistant Director General (PHB)

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1978

का०आ० 3574.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 28 मई, 1977 के पृष्ठ 1916–1921 पर प्रकाशित, भारत सरकार के संचार मंत्रालय (डाक तार बोर्ड) की अधिसूचना सं० का० आ० 1576 तारीख 12 मई, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में :—

(i) क्रम सं० 49 के सामने, स्तम्भ 2 में, "सहायक महाप्रबन्धक" शब्दों के स्थान पर "प्रभागीय इंजीनियर टेलीग्राफ" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) क्रम सं० 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्रम संख्या	अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थान
1	2	3
57	प्रभागीय इंजीनियर टेलीफोन, जिला प्रबंधक टेलीफोन का कार्यालय, चंडीगढ़	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित जिला प्रबन्धक, चंडीगढ़ टेलीफोन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान।
58	प्रभागीय इंजीनियर टेलीफोन, जिला प्रबन्धक टेलीफोन का कार्यालय, सूरत	सूरत की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित जिला प्रबन्धक सूरत टेलीफोन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान।
59	प्रभागीय इंजीनियर टेलीफोन, जिला प्रबन्धक टेलीफोन का कार्यालय, लुधियाना	लुधियाना की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित जिला प्रबन्धक, लुधियाना टेलीफोन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान।
60	प्रभागीय इंजीनियर टेलीफोन, जिला प्रबन्धक टेलीफोन का कार्यालय, बड़ौदा	बड़ौदा की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित जिला प्रबन्धक बड़ौदा टेलीफोन प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान।
61	प्रभागीय इंजीनियर टेलीफोन, जिला प्रबन्धक टेलीफोन का कार्यालय, त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित जिला प्रबन्धक त्रिवेन्द्रम के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान।
62	प्रभागीय इंजीनियर टेलीफोन, जिला प्रबन्धक टेलीफोन का कार्यालय, राजकोट	राजकोट की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित जिला प्रबन्धक, राजकोट के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान।
63	प्रधानाचार्य, डाक तार प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर	प्रशिक्षण केन्द्र के भीतर स्थित प्रधानाचार्य, डाक तार प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान।
64	प्रधानाचार्य, डाक प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा	प्रशिक्षण केन्द्र के भीतर स्थित प्रधानाचार्य, डाक प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान।
65	प्रधानाचार्य, डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मैसूर	प्रशिक्षण केन्द्र के भीतर स्थित प्रधानाचार्य डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मैसूर प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान।
66	प्रधानाचार्य, डाक प्रशिक्षण केन्द्र, बड़ौदा	प्रशिक्षण केन्द्र के भीतर स्थित प्रधानाचार्य, डाक प्रशिक्षण केन्द्र बड़ौदा के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान।

[सं० 2-209/73 एन बी]

ई०जी०एस० सत्यमूर्ति, सहायक महा निदेशक (आर)

New Delhi, the 30th October, 1978

S. O. 3574.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Communications (Posts and Telegraphs Board) No. S.O. 1576, dated the 12th May, 1977, published at pages 1916 to 1921 of the Gazette of India, Pat II—Sections 3—Sub-section (ii), dated thd 28th May, 1977, namely:

In the Table below the said notification:—

(i) against Serial No. 49, in column 2, for the words "Assistant General Manager", the words "Divisional Engineer Telegraphs" shall be substituted;

(ii) after serial No. 56 and the entries relating thereto, th following shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Designation of officer	Public premises
1	2	3
57.	Divisional Engineer Telephones, Office of the District Manager, Telephones, Chandigarh.	Premises under the administraive control of the District Manager, Chandigarh Telephones situated within the local limits of the Union Territory of Chandigarh.
58.	Divisional Engineer Telephones, Office of the District Manager, Telephones, Surat.	Premises under the administrative control of the District Manager, Surat Telephones, situated within the local limits of Surat.
59.	Divisional Engineer Telephones, Office of the District Manager, Telephones, Ludhiana	Premises under the administrative control of the District Manager, Ludhiana Telephones, situated within the local limits of Ludhiana.
60.	Divisional Engineer Telephones, Office of the District Manager, Telephones, Baroda.	Premises under the administrative control of the District Manager, Baroda, Telephones, situated within the local limits of Baroda.

61. Divisional Engineer Telephones, Office of the District Manager, Telephones, Trivandrum.	Premises under the administrative control of the District Manager, Trivandrum Telephones, situated within the local limits of Trivandrum.
62. Divisional Engineer, Telephones, Office of the District Manager, Telephones, Rajkot.	Premises under the administrative control of the District Manager, Rajkot Telephones, situated within the local limits of Rajkot.
63. Principal, P&T Training Centre, Saharanpur.	Premises under the administrative control of the Principal , P&T Training Centre, Saharanpur, situated within the Training Centre.
64. Principal, Postal Training Centre, Darbhanga.	Premises under the administrative control of the Principal, Postal Training Centre, Darbhanga, situated within the Training Centre.
65. Principal, Postal Training Centre, Mysore.	Premises under the administrative control of the Principal, Postal Training Centre, Mysore, situated within the Training Centre.
66. Principal, Postal Training Centre, Vadodava.	Premises under the administrative control of the Principal, Postal Training Centre, Vadodara, situated within the Training Centre.

[No. 2-209/73-NB].

E.G. S. SATHYMOORTHY, Asst. Director-General (R)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1978

का० आ० 3575.—केन्द्रीय सरकार, अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, भीलवाड़ा को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ राजस्थान राज्य के लिये अभ्रक खान कल्याण आयुक्त नियुक्त करती है ।

[फा० सं० ए-11016/3/78-एम० 3]

जगदीश प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 1st November, 1978

S.O. 3575.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (22 of 1946), the Central Government appoints the Welfare Commissioner, Government of India, Bhilwara, as the Mica Mines Labour Welfare Commissioner for the State of Rajasthan for the purpose of the said Act.

[F. No. A. 11016/3/78-MIII]

JAGDISH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1978

का० आ० 3576.—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 30 के स्पष्टीकरण और पैरा 39 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र तारीख 26 सितम्बर, 1964 में प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व सामाजिक सुरक्षा विभाग की अधिसूचना सं० का० आ० 3449 तारीख 18 सितम्बर, 1964 का भागतः उपान्तरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि से परामर्श करने के पश्चात् और कर्मचारी भविष्य निधि के साधनों का ध्यान रखते हुए यह निदेश देती है कि उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा के अन्त में, निम्नलिखित शब्द, अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"किन्तु यह रकम प्रति स्थापन कम से कम पांच रुपए प्रति माह होगी"।

2. यह अधिसूचना दिसम्बर, 1978 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगी।

[सं० एस० 70012/11/78-पी०एफ० (II)

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

New Delhi, the 23rd November, 1978

S.O. 3576.—In exercise of the powers conferred by Explanation to paragraph 30, and by paragraph 39, of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 and in partial modification of the notification of the Government of India in the late Department of Social Security No. S.O. 3449 dated the 18th September, 1964 published in Gazette of India dated the 26th September, 1964 the Central Government, after consulting the Central Board of Trustees, Employees Provident Fund, and having regard to the resources of the Employees Provident Fund hereby directs that at the end of the first paragraph of the said notification the following words shall be inserted, namely :—

"subject to a minimum sum of rupees five per month per establishment."

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of December, 1978.

[No. S-70012/11/78-PF II]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 23rd November, 1978

S.O. 3577.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mohan Colliery of Western Coalfields Limited, Kanhan Area and their workmen which was received by the Central Government on the 21st November, 1978.

BEFORE SHRI S. N. JOHRI, B.Sc., LL.M. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R) (44)/1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of Mohan Colliery of Western Coalfields Limited, Kanhan Area and their workmen represented by Shri Shivbaran Singh, President, Bhartiya Koyla Khadan Mazdoor Sangh (BMS), Chandametta, P.O. Chandametta, District Chhindwara (M.P.).

APPEARANCES :

For Union.—S/Shri Digamberdas Vishwakarma and B. K. Tiwari.

For Management.—S/Shri P. S. Nair, Advocate & P. C. Khare, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mines DISTRICT : Chhindwara (M.P.)

AWARD

Dated : November 15, 1978

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-22012(8)/78-D. IV(A) Dated 16th August, 1978, for the adjudication of the following industrial dispute :—

"Whether the action of the management of Mohan Colliery of Western Coalfields Limited, Kanhan Area in terminating the services of Shri Surajmal, son of Shri Bhiku, General Mazdoor, with effect from 26th October, 1977 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. After the pleadings were filed and issues framed the case was listed for evidence of parties. However, instead of contesting the case the parties have reached the following settlement and prayed that an award be made in terms of the settlement:

TERMS OF SETTLEMENT

1. It was agreed that the workman Shri Surajmal will be reinstated on his original job.
2. As a gesture of goodwill the management agreed to pay Rs. 600 (Rupees Six Hundred only) as lump-sum to the workman.
3. The parties further agreed to file this settlement before the Central Govt. Industrial Tribunal, Jabalpur on 15th November, 1978 and request the Tribunal to pass award in terms of the settlement as above.

3. I find the above terms of settlement as fair and reasonable and make my Award in terms of the settlement. Parties will bear their own costs.

S. N. JOHRI, Presiding Officer
[No. L-22012(8)/78-D. IV(A)]
NAND LAL, Desk Officer

Dated : 15-11-1978.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1978

का० आ० 3578.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1485, तारीख 8 मई, 1978 द्वारा बैंक नोट प्रेस देवास में सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ के लिए 26 मई, 78 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 26 नवम्बर, 1978 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस० 11017/7/78-डी० I(ए०)]

New Delhi, the 25th November, 1978

S. O. 3578.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required, had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1485 dated the 8th May, 1978 the service in the Bank Note Press, Dewas, to be a Public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 26th May, 1978.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 26th November, 1978.

[No. S. 11017/7/78-DI(A)]

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1978

का० आ० 3579.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1641 तारीख 23 मई, 1978 द्वारा कोयला उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ के लिए 27 मई, 1978 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 27 नवम्बर, 1978 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस० 11017/9/78 डी० 1 (ए०)]

एल० के० नारायणन्, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th November, 1978

S.O. 3579.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required, had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 1641 dated the 23rd May, 1978, the Coal Industry to be a Public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 27th May, 1978.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 27th November, 1978.

[No. S. 11017/9/78/DI(A)]

L. K. NARAYANA, Desk Officer

New Delhi, the 28th November, 1978

S.O. 3580.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Ahmedabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workman over the termination of the services of Shri J. S. Shah, temporary Peon, which was received by the Central Government on 24-11-78.

BEFORE SHRI R. C. ISRANI, B.A. (HONS), LL.B.,
INDUSTRIAL TRIBUNAL

Reference (ITC) No. 4 of 1977

ADJUDICATION

BETWEEN

The Management of Bank of Baroda, Ahmedabad.

AND

Their workmen

In the matter of terminating the services of Shri J. S. Shah, temporary peon of Dabhoi branch.

APPEARANCES :

Shri C. V. Pavashkar for the Bank; and
Shri K. R. Mehta for the Workmen.

AWARD PART-II (FINAL)

This is a reference made by the Government of India to this Tribunal under clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, (hereinafter to be referred to as 'the Act'), vide the Government of India, Ministry of Labour's Order No. L-12012/173/76-D, II.A dt. 13th September, 1977, in respect of an industrial dispute which has arisen between the parties, viz., the Bank of Baroda, Ahmedabad, (hereinafter to be referred to as 'the Bank') and the workmen employed under it.

2. The dispute, as it appears from the schedule attached to the original order, under which this reference has been made, relates to the demand, which is as under :—

"Whether the management of Bank of Baroda is justified in terminating the services of Shri J. S. Shah, temporary peon of Dabhoi branch. If not, to what relief is the said workman entitled ?"

3. In support of this demand, the union, by name, All India Bank of Baroda Employees' Union, Nagpur, (hereinafter to be referred to as 'the union') has filed its statement of claim, ex. 3, dt. 30-10-77. It is the case of the union that one Shri J. S. Shah, (who will hereinafter be referred to as 'the workman'), was employed by the bank as a peon at its branch at Dabhoi in District Baroda, Gujarat State. The workman had put in more than 240 days of continuous service from the year 1970-71 onwards. He had continuously worked under the bank till 29-5-1973, on which date his services were arbitrarily discontinued and he was removed from service and consequently was rendered jobless. It is the contention of the union that the workman was appointed against a permanent sanctioned vacancy of a peon in the bank at Dabhoi branch and he was performing the duties of permanent nature. Before the services of the workman were terminated, he was not given either any show cause notice or any retrenchment compensation. It is also alleged by the union that after retrenching the workman, the bank had recruited a new person as a peon, by name, Shri Pravinkumar, who, it is alleged, happens to be a relative of a member of the staff of the Bank at its Dabhoi branch. It is, therefore, urged that the action of the bank in terminating the services of the workman was illegal and unjustified and, therefore, it required to be set aside. Since the bank refused to concede the demand of the union for the reinstatement of the workman, an indusrial dispute was raised and ultimately the Government of India was pleased to refer the present industrial to this Tribunal for its adjudication.

4. On behalf of the bank, the written statement, ex. 8, has been filed on 22-12-77. It is contended that the workman being a temporary peon, would not be legally entitled to file such a claim, or to raise such an industrial dispute. It was also urged that this Tribunal has no jurisdiction to entertain and decide the present reference. It was urged that in fact no industrial dispute existed between the parties and, therefore, no reference could be made of any such dispute to this Industrial Tribunal. According to the bank, the workman was not a member of the above mentioned union and, therefore, also the Government of India was not justified in making the present reference for which there was no justification whatsoever. It is the case of the bank that the workman was appointed on purely temporary basis on account of some increase in work in that branch of the bank and, therefore, as soon as the said work was over, his services came to an end automatically and that the termination of his services under such conditions, would not amount to retrenchment, as contemplated under the Act. It was, therefore, urged that the demand covered by this reference, should not be granted and consequently the reference be rejected.

5. The bank also filed a further written statement, ex. 13 on 22-2-78. Through this additional written statement, some legal pleas against the maintainability of this reference were taken.

6. Thereafter a further additional written statement, ex. 17 was filed on 1-3-78. Through that further additional written statement, the same plea about there being no industrial dispute between the parties, was reiterated. In addition to that, a further plea was also taken that the workman was employed in Dabhoi branch; that in that branch there were in all 23 workmen and they had a separate union, by name, Gujarat Pradesh Karamchari Sangh. It was contended that this industrial dispute has not been raised or espoused by the said union and, therefore, the present reference was not legally maintainable, as the union which had raised this industrial dispute, had no authority to do so. It is urged that the Bank of Baroda Employees' Union does not have any representative character so far as Dabhoi branch is concerned and, therefore, also the said union cannot raise any industrial dispute on behalf of the workmen employed under Dabhoi branch. A further contention was also taken that during the course of conciliation proceedings, no resolution was filed by the Bank of Baroda Employees' Union, Baroda, that they had been authorised either by the workmen of Dabhoi branch to raise an industrial dispute on their behalf in respect of the reinstatement of Shri J. S. Shah, or they had been authorised by the workman himself to raise an industrial dispute on his behalf. It was, therefore, contended by the bank that because the union which raised this industrial dispute before the Government of India, had no legal authority to do so, the present reference would not be legally maintainable.

7. Since the above mentioned legal contentions were taken against the legal maintainability of this reference, an attempt was made on behalf of the bank to get these legal contentions decided in the first instance as the decision on these contentions, if given in favour of the bank, was likely to result in the final disposal of this reference, it was decided to hear the parties in respect of these legal contentions and to dispose of the same before entering into the merits of the claim covered by this reference. Consequently, the learned represenatives of the parties were heard and thereafter Award Part I was made on 25-4-78 rejecting all these legal contentions raised on behalf of the bank against the maintainability of this reference. After disposing of all these legal contentions it was directed that this reference may proceed further on its merits.

8. On behalf of the union Shri K. R. Mehta has appeared in this reference and the bank was represented by Shri C. V. Pavashkar. So far the union is concerned, the evidence of the workman himself has been recorded at ex. 23 and so far as the bank is concerned, the evidence of one Shri Y. P. Bhatt, who was at the relevant time the manager of the Dabhoi branch of the bank has been recorded at ex. 26. Thereafter the union closed its case vide the purshis, ex. 25 dt. 6-7-78 and the bank closed its case vide the purshis, ex. 27, dt. 1-8-78. On behalf of the parties voluminous documentary evidence has been produced which has been exhibited in this reference with their mutual consent. After hearing the learned representatives of the parties and after considering the oral as well as documentary evidence brought on record of this reference, the only short point which would call for determination in this reference would be, "Whether the action of the bank in terminating the services of the workman, with effect from 29-5-73 in the manner it was terminated, can be justified to be legal and proper ? If not, whether a direction can be given to the bank to reinstate the workman in his original position and also to pay him his full back wages ?"

9. It is an admitted position that the workman was appointed as a temporary peon in Dabhoi branch of the bank with effect from 21-1-1971 through oral orders of the then manager of that branch one Shri Y. P. Bhatt. Again, it is an admitted position that his services were terminated with effect from 29-5-1973, again through oral orders without giving him any previous notice, charge sheet or any other warning. Now, it may be pointed out at the very out set, that even this procedure adopted by the authorities of the bank, in appointing the workman as a temporary peon, and again in terminating his services in the manner stated above, was illegal and in contravention of the provisions of Sastry Award which was made in respect of the conditions of services of the workmen employed by the banking industry in India. In this connection, attention is invited to para 495 on p. 138 of Sastry Award, contained in the blue booklet entitled 'All India Industrial Tribunal (Bank Disputes) Award' which clearly lays down as under :

> "We further direct that on a candidate's appointment as a temporary employee, a probationer or a permanent member of the staff, the bank shall give him a written order specifying the kind of appointment and the pay and allowances to which he would be entitled and that such a written order shall be given on the appointment of a part-time employee also."

Shri Y. P. Bhatt, who is examined on behalf of the bank at ex. 26, has admitted during his cross examination that no appointment letter was given to Shri Shah at any time. He has further admitted that no written orders were given to him whenever his services were terminated. It is thus clear that even at the time of making his appointment at the initial stage, the bank had violated the mandatory provisions of the Sastry Award as contained in para 495. In this connection, a reference is also invited to para 522 of the said award on p. 145 of the same booklet. Sub-clause (4) of that para of the said award reads as under :

> "(4) The services of any employee other than a permanent employee or probationer may be terminated, and he may leave service, after 14 days' notice. If such an employee leaves service without giving such notice he shall be liable for a week's pay (including all allowances)."

It is clear from this provision under that award that before the services of even a temporary employee of the bank can be terminated, a 14 days' notice has to to be given to him in writing. In this connection, a reference will have also to be made to sub-clause (5) of that para 522 in that award which reads as under :—

> "(5) An order relating to discharge or termination of service shall be in writing and shall be signed by the manager. A copy of such order shall be supplied to the employee concerned."

Admittedly, neither any such order was passed by the authorities of the bank at the time of terminating the services of the workman with effect from 29-5-73, nor any such order in writing was given to him by the bank. It is thus fully established that the mandatory provisions of paras 495 and 522(4) and 522(5) of the above mentioned award were flagrantly violated by the authorities of the bank in terminating the services of the workman. This clearly establishes the illegality committed by the bank authorities at both the points of time, viz., at first at the time of appointing the workman and on second time at the time of terminating his services. There is no difficulty in finding out the reason as to why this illegal procedure was adopted by the authorities of the bank in dealing with the workman. It clearly appears that the then manager of Dabhoi branch of the bank appears to have treated the said branch of the bank as if it was his private institution or firm for which he could recruit any person at any time and again could dispence with his services at his own sweet will and without following any procedure prescribed in that connection. The action of the then manager clearly appears to be absolutely arbitrary and in contravention of the established conventions, precedents, rules, agreements or awards made between the management of the bank and the workman employed by the bank. On this ground alone the action of the management of the bank in terminating the services of the workman in the manner in which they were terminated, can be legitimately declared to be illegal justifying a direction that the workman be reinstated in his original position.

10. Apart from the above mentioned defect in the orders of terminating in respect of the workman, if the case of the workman is closedly examined, it would clearly appear that there has also been breach of the mandatory provisions of Section 25F of the Act because the termination of services of the workman with effect from 29-5-73, would amount to his retrenchment but the conditions precedent to effecting any such retrenchment as laid down in the above mentioned section of the Act, were neither followed nor complied with. There is no dispute between the parties that after the workman was initially appointed with effect from 21-1-71, there were various breaks in his service ranging from one day to even 2¼ months. On examining the reasons for such break, it appears that these breaks were effected artificially in order to deprive the workman of the right to have put in a continuous service on this aspect of the union's case, the bank's witness Shri Y. P. Bhatt has been examined at ex. 26. To a question from the union representative Shri K. R. Mehta, this bank officer gave the following admission :—

> "According to our instructions from the higher authorities after every 90 days continuous services his service used to be discontinued for about 3 days. Similarly for every break the duration used to be about 3 days. At the time of terminating his services after continuous service of 90 days he used to be orally instructed to again report for duty after 3 days. He was not given 14 days notice before his services were terminated as a temporary peon. No pay was given to him in lieu of such notice."

Can there be any more dishonest behaviour on the part of an employer as had been the behaviour of the authorities of the bank in this case when only for the purpose of depriving the workman to claim a continous service as contemplated in the Act, artificial breaks were given to him after the completion of 90 days' continuous service and again he was instructed at the time of discontinuing his service, that he should come and join the same service in the same capacity after a lapse of 3 days ? This is really regrettable that an institution like the bank, which can have no personal interest similar to an individual employer, should have acted in this undesirable and disgraceful manner. If actually the services of the workman were to come to an end on account of there being no necessity to continue his employment, or on account of he having become an extra or spare hand, then, there would have been no necessity of telling him at the very time of terminating his service that he should come back and join his duty after the lapse of 3 days. This action definitely amounts to a manoeuver to get rid of the provisions of the Act and actually to subvent them to the prejudice of the workman. There would therefore be absolutely no difficulty in holding that whatever breaks had occurred in the otherwise continuous service of the workman in the bank, the same were only artificial breaks which were effected with a mala fide intention of depriving the workman of his legitimate benefits of his otherwise continuous service under the bank.

11. Shri K. R. Mehta on behalf of the union has given the details of the dates on which the workman was initially appointed and was subsequently, from time to time discharged from service and was again re-employed in the service. It will be necessary to give these details in this award for the purpose of appreciating ultimately, as to whether, in the given circumstances and on the facts which are uncontroverted, it can be held that the service of the workman under the bank can be or would be deemed to be continuous service as contemplated in the Act ? These details which have neither been challenged nor controverted on behalf of the bank and which also received support from the documents of the bank itself at exs. 14/1 and 24 as under :

The date of 1st appointment of the workmen : 21-1-71	The date of 1st appointment of his service : 24-4-78

The date of 2nd re-employment of the workman		27-4-71	The date of 2nd termination of his service		26-7-71
-do-	3rd	2-8-71	-do-	3rd	1-11-71
-do-	4th	18-1-72	-do-	4th	30-5-72
-do-	5th	1-6-72	-do-	5th	30-6-72
-do-	6th	2-9-72	-do-	6th	30-9-72
-do-	7th	11-11-72	-do-	7th	10-2-73
-do-	8th	20-2-73	-do-	8th (final)	29-5-73

12. Now what is "continuous service," has been defined in Section 25B of the Act. That section has again two sub-sections. Sub-section (1) is to the following effect :

"25B. For the purpose of this Chapter,—

(1) a workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service, including service which may be interrupted on account of sickness or authorised leave or an accident or a strike which is not illegal, or a lock-out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the workman ;"

So far the provisions of this sub-section (1) of Section 25B of the Act are concerned, the present case of the workman would not be governed by this provision, so as to attract the application of the provisions of Section 25F of the Act, which relate to the retrenchment of workmen, because on the consideration of the different periods of service of the workman, it cannot be held that he had put in a continuous service of not less than one year under the bank. However, the case of the workman would be clearly covered by sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (2) of Section 25B of the Act. It will therefore be necessary to reproduce these provisions which are as under :

"25B. For the purposes of this Chapter,—

(1) *** ***

(2) where a workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer—

(a) for a period of one year, if the workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with reference to which calculations is to be made, has actually worked under the employer for not less than—

(i) one hundred and ninety days in the case of a workman employed below ground in a mine ; and

(ii) two hundred and forty days, in any other case ;"

13. Keeping the above mentioned provisions of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (2) of Section 25B of the Act in view, it will have to be found out from the details of service of the workmen under the bank, whether his service shall be deemed to be continuous service under the bank ? The date of the last termination of his service was undoubtedly 29-5-1973. As such, that would be the date with reference to which calculation has to be made in order to find out, whether the case of the workman would fall under the above mentioned provisions of Section 25B(2) of the Act ? From 29-5-1973, 12 calendar months immediately preceding that date will have to be kept in view. As such, it will have to be found out, whether between 30-5-1972 and 29-5-1973, the workman had actually worked under the bank for not less than 240 days irrespective of there having occurred any breaks in his service ? The details given above about his service would indicate that the fourth termination of his service had occurred on 30-5-1972. Thereafter he was again re-employed with effect from the next date, i.e. from 1-6-72 and had worked upto 30-6-72. He had, therefore, actually worked for 30 days from 1-6-72 to 30-6-72. Again, he was re-employed with effect from 2-9-72 and had continuously worked upto 30-9-72, which would show that he had worked for, in all 27 days. He was again re-employed with effect from 11-11-72 and had continuously worked upto 10-2-73 on which date his services were terminated He had, therefore, actually worked during that period for 92 days. He was again re-employed on 20-2-73 and had continuously worked upto 29-5-73 on which date his services were finally terminated. He had, therefore, actually worked during that period for 99 days. When we total all these days, viz., 30.+27+92+99, the figure would come to 248 days. It is thus fully estab ished that the workman had actually worked under the employer, viz., the bank for not less than 240 days during a period of 12 calendar months immediately preceding the date with reference to which calculations are to be made, i.e. the date of his last termination, viz., 29-5-73. If that is so, under the provisions mentioned above, the services of the workmen under the bank, shall be deemed to be continuous and he shall be deemed to have been in continuous service of the bank during that period.

14. If that is so a reference shall have to be made to the provisions of section 25F of the Act which lays down the conditions precedent to the retrenchment of workmen who have been in continuous service of the employer for not less than one year. It will be necessary to reproduce the said provisions of Section 25F which are as under :

"25F. No wokman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—

(a) the workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice :

Provided that no such notice shall be necessary, if the retrenchment is under an agreement which specifies a date for the termination of service :

(b) the workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay or every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months ; and

(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government for such authority as may be specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette."

15. It is an admitted position as stated above and as also discussed from the evidence of the bank's witness Shri Y. P. Bhatt examined at ex. 26, that before terminating the services of the workman neither any written order nor any previous notice was given to him. The 3 conditions as contained in clauses (a), (b) and (c) of Section 25F of the Act, were admittedly not followed before retrenching the workman from the service of the bank. If that is so, the action of the authorities of the bank in terminating the services of the workman which termination undoubtedly amounts to his retrenchment, cannot be legally justified because it was taken in violation of the provisions of Section 25F of the Act which provisions are mandatory and are required to be followed before effecting the retrenchment. It is by now well settled position of law, so far as industrial disputes are concerned. that if the order of retenchment is held to be illegal, as has been held in this case, the normal order would be the reinstatement of the illegally retrenched workman with the payment of his full back wages minus the wages which he may have earned during the course of his re-employment under the original employer. An attempt was made on behalf of the bank to show that in fact there was no vacancy either permanent or temporary of a peon in Dabhoi branch of the bank when the workman was employed as a peon. A very clever effort has been made to arouse the sympathy of this

Tribunal by saying that the then Manager of the Dabhoi branch of the bank was guided by humanitarian and sympathetic considerations for the family of the workman when he graciously called him and appointed him as a peon in the bank, but later on these sentiments seem to have evaporated or vanished when the authorities found that the workman was no more a desirable person to be continued in the service of the bank. In this connection, it will be interesting to refer to the evidence of Shri Bhatt examined on behalf of the bank at ex. 26. During his examination-in-chief he has stated while referring to the employment of the workman, as under :—

> "He was employed on account of pity and mercy on his family but otherwise he was having a peculiar and strange temperament and was therefore not fit to be kept in the employment of the bank."

At an early stage he stated as under :—

> "Shri Shah was appointed because his family was very needy and because the persons from the locality where he lived recommended his case on human considerations."

At a subsequent stage he condemned the workman in following words :

> "He had no manners how to deal with the bank officers and customers. He had the audacity on one of the occasions to test the tea before giving it to the guest for whom it was meant. He was not performing his duties properly. It was therefore that his services were terminated."

16. No rules, regulations, circulars or instructions issued by the bank have been produced to show that a manager of a branch of the bank can legitimately, locally appoint a person on humanitarian considerations or on account of the feelings of pity for the family of a particular person. Even if it were to be accepted for the sake of arguments, that on the considerations of higher values of life and the sentiments of pity and sympathy such appointments can be made, then also, it is to be seen, whether after having made such appointments, the other procedure, rules and regulations regarding the termination of services of bank employees are to be thrown to the winds and are not to be respected and followed ? There is nothing in the Act and the rules as well as in various settlements, awards including Sastry Award which can indicate that if persons are employed in the bank on the considerations on which the workman is said to have been employed, the procedure or rules prescribed laying down the mandatory provisions to be followed at the time of terminating their services, are not to be complied with. Again, it is not correct to say that the said manager of the Dabhoi branch had voluntarily of his own free will appointed the workman as a peon in that branch of the bank. There is on record of this reference, an application dated 24-6-71 which is ex. 28/1. It shows that the workman had addressed that application to the Regional Manager, Bank of Baroda, Baroda Region, Baroda for appointment as a peon on a permanent basis. As such, there was a definite request from the workman in that connection and the said request was addressed to the Regional Manager of the Bank. The claim of the bank that even though there was no post for any additional peon, yet, on account of humanitarian considerations, the workman was appointed as a peon is also not borne out from the facts on record. The bank register produced at ex. 11 (1-A) shows at its page 23 that one peon from Dabhoi branch of the bank had been transferred in these days and obviously there was a clear vacancy on which the workman was appointed. That the vacancy on which the workman was appointed was a clear vacancy of permanent nature is substantiated even from one other independent circumstance because after the services of the workman were terminated, immediately, one Shri Pravin Pandya was freshly recruited as a peon and appointed in that vacancy on which the workman was working as a peon. If the post on which the workman was appointed was an extra post in addition to the permanent posts of peons sanctioned for that branch of the bank, after the termination of his services, it would not have been necessary to again bring in a fresh man by continuing that additional post of the peon. It cannot be denied and no such contention has been taken on behalf of the bank, that the provisions of Section 25F of the Act, relating to the conditions precedent to retrenchment of workman, would also cover the case of even temporary workman. In this connection, a reference may be made to the provisions of Section 2(oo) of the Act which defines 'retrenchment'. They are as under :

> "2. (oo) "retrenchment" means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include—
> (a) voluntary retirement of the workman; or
>
> (b) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf; or
>
> (c) termination of the service of a workman on the ground of continued ill health."

17. From this definition it will appear that termination by the employer of the services of a workman for any reason whatsoever otherwise as contemplated under these provisions, would amount to retrenchment. The definition does not say that the workman should be a permanent workman or that he should not be a temporary workman and again the words 'for any reason whatsoever' are very wide and they would cover the case of even the persons whose services are terminated even by efflux of time. In this connection a reference is invited to a decision of the Supreme Court of India reported in 1976-I L.L.J. 478 in the case between State Bank of India and N. Sundaramoney. The question which was for the consideration of the Supreme Court of India in that case was whether the respondent was retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the Act ? What was held has been indicated in para 9 of the judgement on p. 481 which is as under :

> "Without further ado, we reach the conclusion that if the workman swims into the harbour of S. 25F, he cannot be retrenched without payment, at the time of retrenchment, compensation computed as prescribed therein read with S. 25B(2)."

The present case, therefore, is completely covered by the above mentioned decision of the Supreme Court of India and, therefore, even if the services of the workman were terminated because they were no more required or that he was not found to be suitable for the same, then too, the termination would amount to 'retrenchment' and because the mandatory provisions of Section 25F of the Act were violated, the action of the management would be declared to be illegal and ultimately the same will have to be set aside. The other decision which may be cited in this connection is reported in 1976 LAB.I.C. on p. 1766 in the case of M/s. Hindustan Steel Ltd., v/s. The Presiding Officer, Labour Court, Orissa and others. The relevant observations are on p. 1768 and they are to the following effect :

> "It may also be noted that Section 25F(a) which lays down that no workman who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenchment by that employer unless he has has been given one month's notice or wages in lieu of such notice, has a proviso which says that "no such notice shall be necessary if the retrenchment is under an agreement which specifies a date for the termination of service." Clearly, the proviso would have been quite unnecessary if retrenchment as defined in Section 2(oo) was intended not to include termination of service by efflux of time in terms of an agreement between the parties. This is one more reason why it must be held that the labour court was right in taking the view that the respondents were retrenched contrary to the provisions of Section 25F."

In para 2 of the said judgement, Their Lordships of the Supreme Court of India were pleased to observe as under :

> "2. The main question in this appeal is whether the three respondents had been retrenched by their employer as found by the Labour Court. If these were cases of retrenchment, the order of reinstatement made by the Labour Court was obviously a valid order as, admittedly, the condition precedent to the

retrenchment of workmen laid down in Section 25F of the Industrial Disputes Act had not been satisfied."

From these observations it will appear that if in any particular case it is held on merits, that the termination of services amounted to retrenchment and if the mandatory provisions of Section 25F of the Act had not been followed, then, the normal order would be the reinstatement of the retrenched workman with the payment of full back wages, minus of course, any amount which it is proved that he had earned during the period of his unemployment under the original employer. In this case, therefore, the only reasonable, proper and legitimate order which can be made would be, to direct the reinstatement of the workman in his original position as a peon in Dabhoi branch of the bank.

18. As regards the back wages, the workman has been examined at ex. 23 in this reference. During his Examination-In-Chief he deposed on oath that after the termination of his services from the bank, he had tried to secure other service, but had not succeeded. This statement of the workman has not been assailed during his cross examination and the bank has not been able to place before this Tribunal even a suggestion that the workman was gainfully employed elsewhere during the above mentioned period from 29-5-73 onwards. In view of this position, this is a fit case in which along with the reinstatement of the workman, a furher direcion will have to be given that he should also be paid his full back wages including all allowances which he was drawing immediately before the date of the termination of his service, viz., 29-5-73.

19. (i) It is, therefore, hereby directed that the workman Shri J. S. Shah be immediately reinstated in his original position as a peon in Dabhoi branch of the bank, the termination of his service having been declared to be illegal.

(ii) It is also directed that he should be paid his full back wages including all allowances which he was drawing on the date of the termination of his services, i.e. 29-5-73, with effect from 29-5-73 till the date on which he is actually reinstated in his original position.

(iii) The arrears of back wages becoming due to the workman, shall be paid to him within a period of one month from the date of the publication of this award in The Gazette of India.

(iv) The first party to bear its own costs and also to pay the costs of the second party which are quantified at Rs. 500/-.

Sd/- M. P. BAROT, Secretary,

Ahmedabad, dated the 7th Nov., '78.

Sd/- R. C. ISRANI, Presiding Officer.

[No. L-12012/173/76-D.II.A.]

R. P. NARULA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978